

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 475] No. 475] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2013/भाद्र 26, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2013/BHADRA 26, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशालय)

(सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2013

विषय : —सोडियम नाइट्राइट के आयातों से सम्बंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम जांच परिणाम ।

सा.का.नि. 637(अ).—जी एस आर डी-22011/03/2013 दिनांक 17/09/2013 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हए;

। प्रक्रिया

- 1. मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने अपने परामर्शदाता मैसर्स टीपीएम सालिसिटर्स एंड कन्सल्टेन्ट्स के माध्यम से सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतद्पश्चात् रक्षोपाय नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदनपत्र भारत में 'सोडियम नाइट्राइट' के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए दायर किया है जिससे कि भारत में सोडियम नाइट्राइट के संवर्धित आयातों के द्वारा कारित की जा रही गम्भीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके।
- 2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा

(1)

4021GI/2013

तक किया गया। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 के अंतर्गत सभी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, भारत में सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत का नोटिस सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को जारी किया गया और उसी दिन इसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

3. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति के साथ केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय एवं अन्य सम्बंधित मंत्रालयों, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और निम्नलिखित सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(3) और 6(2) के अनुसार भेजी गई:

(i) घरेलू उत्पादक

- क. मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, दीपक काम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, नेशनल गेम्स रोड, पुणे-411006
- ख. पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (जिसे अब पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)-160022
- ग. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-231301 (उत्तर प्रदेश)
- घ. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, प्रियदर्शनी, 7वां तल, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सायन, मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400022

(ii) आयातकर्ता

- क. अहमदाबाद कैमिकल्स, प्लाट नं.10/7, फेज-।, जी आई डी सी वात्वा, अहमदाबाद- 382445
- ख. एशियाटिक इंडस्ट्रीज, 1505, डीआईडीसी, फेज-।, नरोदा, अहमदाबाद-382330
- ग. एरीज डाइकेम इंडस्ट्रीज, सी-1/260, फेज-II, जी आई डी सी, वात्वा, अहमदाबाद-382445
- घ. बाकुल ऐरोमैटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, स्टर्लिंग सेण्टर, चतुर्थ तल, 16/2 डा. एनीवेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018
- ड. बी आई मेहता, 2-बी, गंगा विहार, 94 काजी सईज स्ट्रीट, बम्बई-400003
- च. कफील प्राइवेट लिमिटेड, 52 नरीमन भवन, नरीमन प्वांइट, मुम्बई-400021
- छ. डिन्टेक्स डाईकेम लिमिटेड, एस पी हाउस, 14 विद्याविहार कालोनी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद-380013
- ज. डायनामिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 43 चतुर्थ तल, न्यूयार्क टावर, ''क", निकट थाल्टेज क्रास रोड, अहमदाबाद-380054
- झ. इन्जेल कैम. (आई) प्रा. लिमिटेड, 159 सीएसटी रोड, कलीना, सांताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400098
- ञ. फार्मसन फार्मास्युटिकल्स गुजरात लिमिटेड, 5वां तल, कामर्स सेण्टर, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005
- ट. इण्डोकोल कैम. लिमिटेड, वैभव बिल्डिंग, निकट गंगा जमुना फ्लैट्स, कैम्प रोड, शाही बाग, अहमदाबाद-380004
- ठ. आईलैण्ड वीरकैमी. ए-4, कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालानगर, हैदराबाद-500037
- ड. जैनसन लिमिटेड, 101, जौली भवन नं.1, 10 न्यू मरीन लाइन्स, मुम्बई-400020
- ढ. केतुल कैम. प्राइवेट लिमिटेड 114/115, दत्तानी ट्रेड सेण्टर, चन्द्रावरकर सेड, बोरीवली (पश्चिम) मुम्बई-400092

- ण. मैट्रोकेम इंडस्ट्रीज, 508/509, शिप बिल्डिंग, सीजी रोड, नरवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009
- त. मनीष कैमिकल्स, सी-1/343, निकट डेवरसन, जीआईडीसी ओधाव, अहमदाबाद-382410
- थ. पारिसन कैमिकल्स लिमिटेड 6-3-347/22/ख, द्वारकापुरी कालोनी, निकट साईबाबा मंदिर, हैदराबाद-500082
- द. प्रभा एक्सपोर्ट्स 301, एरियन, पंजगुट्टा, हैदराबाद-500082
- ध. रवि डाइवियर कम्पनी लिमिटेड, 121, अटलांटा, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021
- न. रोहा डाईकैम, सूर्योदय मिल कम्पाउण्ड, एम पी मिल रोड, ताड़देव, मुम्बई-400034
- प. सवाकाशी डाई-ओ-फैब, प्लाट#1503, जी आई डी सी फेज-।, नरोदा, अहमदाबाद-382330
- फ. एस यू-वाइ कैमिकल्स लिमिटेड, बी-10, एमआईडीसी, अक्कालोठ रोड, शोलापुर-413006

(iii) निर्यातक

- क. हीबेई जिंगझिंग ब्यूरो आफ माइन्स, फेन्ग्शान कैमिकल फैक्टरी साउथ फेन्ग्शा, जिंगझिग माइन्स, शिजियाझुआंग, हीबेई प्राविन्स, चीन।
- ख. शैन्क्सी जियाओचेंग हागजिंग कैमिकल कम्पनी लिमिटेड, सी 904 जिन गण इंटरनेशनल कामर्शियल सेण्टर, सं.91, बिंग झाऊ रोड, ताई युआन, शाक्सी चीन
- ग. शैन्डांग झुचेंग झांग्टाई कैमिकल कम्पनी लिमिटेड, सं. 505, क्विंग पिंग भवन फुगौंग गार्डेन झुचेन्ग शैन्डांग-262200 चीन
- घ. क्रियाडाओ हेग्युआन कैमिकल्स कंपनी लिमि, पेन्ग्हे रोड 2, जिआओनान सिटी शांगडांग प्राविन्स, चीन
- ड. फुशान टाउन वीचेंग जिला, वीफैंग, शान्डांग, चीन
- च. चाइना नेशनल एंड कैमिकल्स आई/ई कार्प. गुइझाड़, युन्नान, चीन-550001
- छ. वुहान कैमिकल्स आई/ई कार्प. ब्लाक-48, वैग सैंग जिला, हन्कोउ, वुहान, चीन-430022
- ज. युन्नान प्राविन्शियल कैमिकल्स आई/ई कारपोरेट, डांग जिया वैन बिल्डिंग, डांग फेंग डैंग लु, कुन्मिंग, युन्नान, चीन
- झ. जियांग्मेन कैमिकल्स आई/ई कंपनी आफ गुआंगडांग चाइना, नं. 84-54, गान्ग्खुओऊ रोड, जियांग्मेन, गुआंग्डांग चीन।
- ञ. कुन्मिंग इम्पोर्ट् एंड एक्सपोर्ट कारपोरेट, 250, हुआन चेंग बेई रोड, कुन्मिंग, चीन
- ट. चाइना हुनान कैमिकल्स इम्प 7 एक्सप. कारपोरेट सं.41 वायी रोड (पश्चिम) चांग्शा हुनान, चीन-410011
- ठ. शैन्ग्क्शी जिआओचेग हान्ग्क्शिंग, कैमिकल कंपनी लिमिटेड, 14वां तल, शुइगांग बिल्डिंग नं.368 **क्विचिन्ग्रिश्यान** नार्थ स्ट्रीट ताइयुआन, शौन्वशी, चीन
- ड. बी ए एस एफ एक्टिंगेसेल्शैफ्ट कार्ल बोस स्ट्रैस्सी 38, 67056 लुडिवग्शैफेन, जर्मनी
- ढ. मैसर्स टेरा नाइट्रोजन (यूके) लिमिटेड पी ओ बाक्स 90 रेडिक्लिफ क्रीसेन्ट, थार्नाबी स्टाकटान-आन-टीज, क्लीवलैण्ड टीएए 176 बी एस

(iv) निर्यातकर्ता राष्ट्र

- क. कोरिया गणराज्य का राजूदातावास, 9 चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली
- ख. जर्मन संघीय गणराज्य का राजदूतावास सं. 6/50जी शांति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

- ग. चाइना जनवादी गणराज्य का राजदूतावास सं. 50-डी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 4. प्रश्नाविलयां ज्ञात निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोगकर्ताओं और उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे अपने विचारों से इस जांच शुरुआत के नोटिस के 30 दिनों के अंदर लिखित रूप से अवगत कराएं।
- 5. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए
- क. आयातक: मैसर्स सन्दीय आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 104, नैन कृपा 118/122 काजी शईद स्ट्रीट, बगगाडी मस्जिद (पश्चिम) मुम्बई-400003
- ख. निर्यातकर्ता राष्ट्र/संगठन: ट्रेड एंड इकनामिक सेक्सन, डेलीगेशन आफ यूरोपियन यूनियन टू इंडिया, 65 गोल्फ लिंक, नई दिल्ली
- ग. निर्यातक राष्ट्र: मिनिस्ट्री आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री,पी ओ बाक्स 1774, एयरपोर्ट रोड, रियाद, 11162 किंगडम आफ सऊदी अरेबिया सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया ।
- 6. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया:
- क. **घरेलू उद्योग**: मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, दीपक काम्प्लेक्स, शास्त्रीनगर, नेशनल गेम्स रोड, पुणे-411006
- ख. **आयातक:** मैसर्स संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड, 104, नैन कृपा 118/122 काजी सईद स्ट्रीट, वैडगाड़ी, मस्जिद (पश्चिम) मुम्बई-400003
- 7. जांच शुरुआत नोटिस के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से भी प्रस्तुतिकरण प्राप्त हुए:
- क. **आयातक:** मैसर्स इन्जाल कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड 6/159 मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट, सर.एम.वी.रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-72
- ख. **आयातक:** मैसर्स संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड, 104, नैन कृपा 118/122 काजी सईद स्ट्रीट, वैडगाड़ी, मस्जिद (पश्चिम) मुम्बई-400003
- ग. **निर्यातक राष्ट्र/संगठन**: ट्रेड एंड इकनामिक सेक्सन, भारत को यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, 65 गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003
- घ. **निर्यातक:** मैसर्स बीएएसएफ एसई 67056 लुडिवग्शैफेन जर्मनी अपने इंडियन काउण्टरपार्ट मैसर्स बीएसएफ इंडिया के जरिए।
- 8. मिनिस्ट्री आफ इकनामी, यूएई, से भी उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माने जाने का अनुरोध उनके दिनांक 04.06.2013 के पत्र के तहत प्राप्त हुआ परंतु उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह विहित समय के अंदर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि रक्षोपाय सम्बंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुपालन के सम्बंध में किए गए उनके प्रस्तुतिकरण अर्थात् इस मामले में रक्षोपाय साध्नों के अंतर्गत न्यूनतम के प्रावधान, को रिकार्ड में ले लिया गया। एक दूसरा प्रस्तुतिकरण ताईवान से ताईपाई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली के जरिए प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल उन्हें न किया जाए परंतु यह अनुरोध किया कि रक्षोपाय सम्बंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 9.1 अर्थात् रक्षोपाय साधन के न्यूनतम प्रावधान को, इस मामले में लागू किया जाना चाहिए।
- 9. इस जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड चण्डीगढ़ (जिसे पहले मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) ने अपने दिनांक 9 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत घरेलू उद्योग का समर्थन किया। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन,

बिक्री और मालसूची के संबंध में आंकड़े प्रदान कराए; उन पर विचार किया गया तथा क्षति विश्लेषण के लिए उनको रिकार्ड में लिया गया।

10. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों पर उपयुक्त निर्धारण करने के लिए विचार किया गया। अधिप्राप्त या प्राप्त अगोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

॥ हितबद्ध पक्षकारों के विचार (जांच शुरुआत नोटिस के पश्चात्)

i किंगडम आफ सऊदी अरेबिया के विचार

- 11. उन्होंने निम्नवत प्रस्तुतिकरण किया:
- क. किंगडम आफ सऊदी अरेबिया से संबंधित उत्पाद का पिछले तीन वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया गया।
- ख. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसरण में किंगडम आफ सऊदी अरेबिया से सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर रक्षोपाय साधनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii यूरोपियन यूनियन के विचार

- 12. संवर्धित आयात
- क. वर्ष 2012-13 के दौरान आयातों में भारी वृद्धि का दावा पिछले 9 माह की उस आयात सांख्यिकी पर आधारित है जिसे वार्षिकीकृत किया गया है। जांच परिणाम वास्तविक आयात मात्रा पर आधारित होना चाहिए।
- ख. आयातों में वृद्धि के लिए चीन को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसके आयातों में 65 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अन्य देशों (जर्मनी) से आयातों में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। भारत को सभी देशों के खिलाफ जांच शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
- 13 क्षति एवं नुकसान :
- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं उसकी बिक्री मात्रा संपूर्ण विश्लेषण अवधि के दौरान स्थिर बनी रही।
- ख. याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच कम हो गया क्योंकि संस्थापित क्षमता 31,000 मी.टन से बढ़कर 41000 मी.टन हो गई थी। उन्होंने 18000 मी.टन से अधिक की बेशी क्षमता भी स्थापित कर ली है जो कुल मिलाकर समस्त स्थानीय मांग से बहुत अधिक थी।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना नहीं हो सकता है कि घरेलू उत्पादक ही कुल घरेलू मांग की आपूर्ति करें। फिर भी, इस मामले में, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अत्यधिक संवर्धित संस्थापित क्षमता अब घरेलू मांग से कहीं अधिक है।
- घ. वर्ष 2012-13 में बढ़े हुए आयातों और वित्तीय स्थिति में गिरावट, जो स्वयं याचिकाकर्ता के अनुसार वित्त वर्ष 2010-2011 से प्रारंभ हई, के बीच कोई संबंध नहीं है।

iii संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड (आयातक) के विचार

- 14. उन्होंने निम्नवत प्रस्तुतिकरण किया:
- क. वे केवल चीन के सामान का ही आयात करते हैं।
- ख. उन्होंने 19 मार्च, 2012 से 875 मी.टन का आयात किया है।
- ग. उनकी सीआईएफ कीमत 476 अम.डा. प्रति मी.टन से 530 अम.डा. प्रति मी.टन के बीच बैठती है।
- घ. आयातों की उतराई लागत 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क के कारण उच्च है।
- ड. घरेलू और आयातित सामान के बीच तकनीकी विनिर्दिशनों में अंतर है।
- च. चीन के उत्पादों में नमी संघटक अधिक है। जबिक, घरेलू उत्पाद में अधिकतम 1 प्रतिशत नमी होती है, चीन के उत्पादों में अधिकतम 1.4 प्रतिशत नमी होती है।
- छ. शुल्क आधार अंतर्वस्तुओं, शुद्धता, लौह एवं जल में अधुलनशील अंतर्वस्तु में भी अंतर होता है।
- ज. आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक है।

- झ. घरेलू उद्योग में इसका उत्पादन करने की समस्या है।
- ञ. घरेलू उद्योग एकाधिकार सृजित करना चाहता है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क भी लगा हुआ है।
- ठ. घरेलू उद्योग शेयर बाजार में लाभ प्रदर्शित कर रहा है।
- ड. खपत बहुत अधिक है।

iv मैसर्स इन्जाल कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड (प्रयोगकर्ता उद्योग) के विचार

- 15. उन्होंने निम्नवत प्रस्तुतिकरण किया है:
- क. उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने उत्पादन के लिए विचाराधीन उत्पाद की किसी भी मात्रा का आयात नहीं किया है।
- ख. वे इस उत्पाद पर, जो घरेलू रुप से उपलब्ध है विदेशी मुद्रा की वचत करने के लिए आयात प्रतिबंध अधिरोपित करने का समर्थन करते हैं, परंतु इन प्रतिबंधों से घरेलू विनिर्माताओं द्वारा बाजार में कमी की परिस्थिति का सृजन न किया जाए और उपभोक्ताओं से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक कीमत प्रभारित न की जाए।

V मैसर्स बीएएसएफ, एसई, जर्मनी (निर्यातक) के विचार

- 16. उन्होंने प्रस्तुतीकरण किया कि निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है:
- क. पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने यूरोपियन यूनियन से सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर दिनांक 23.3.2013 की अधिसूचना के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच पहले ही प्रारंभ कर रखी है।
- ख. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 का नियम 8 घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने से संबंधित है।

III सार्वजनिक सुनवाई

- 17. दिनांक 12 अगस्त, 2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया, इसके लिए हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 25 जुलाई, 2013 को नोटिस भेजा गया। तथापि, घरेलू उद्योग की ओर से केवल मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड और भारत में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ट्रेड एंड इकनामिक सेक्सन द्वारा ही इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया गया। भारत में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने कोई मौखिक प्रस्तुतिकरण नहीं किए।
- 18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को, जो सार्वजनिक सुनवाई में प्रतिभागिता करते हैं, अपने मौखिक रुप से अभिव्यक्त विचारों का सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लिखित प्रस्तुतिकरण दायर करना अपेक्षित होता है। तत्पश्चात, एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाती है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का भी अवसर प्रदान कराया जाता है। इस सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक प्रस्तुतिकरण किए गए, तत्पश्चात उन्होंने लिखित प्रस्तुतिकरण भी किए जबिक यूरोपियन कमीशन नामक केवल एकमात्र अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसने इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया, उसने न तो कोई लिखित प्रस्तुतिकरण ही दायर किया और न ही घरेलू उद्योग द्वारा किए लिखित प्रस्तुतिकरण की कोई प्रत्युक्ति दायर की। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण रिकार्ड में लेकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया परंतु विहित समय समाप्त हो जाने के पश्चात भी उनमें से किसी ने भी प्रत्युत्तर नही दिया। जांच की शुरुआत के पश्चात अथवा सुनवाई के पश्चात सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित रुप में अभिव्यक्त सभी विचारों की जांच की गई और सम्चित निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया।

IV घरेलू उद्योग द्वारा किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण

19. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया:

- क. विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्राइट (एनएएनओ₂) है। यह एक आक्सीडाइजिंग एवं रिडयुसिंग एजेंट होता है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्लीकृत चूर्ण होता है जिसका अधिकांश प्रयोग फार्मास्युटिकल उद्योग में पैरासिटमाल, एनाल्जीन, थायोफिलाइन, केफीन, रंग उद्योग, लुब्रिकेन्ट्स उद्योग, विनिर्माण रसायन उद्योग, रबड़ ब्लोइंग एजेंट; ताप अंतरण लवण, मांस प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र आदि का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क सीटीएच वर्गीकरण कोड 2834.1010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ख. याचिकाकर्ता मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का उत्पादन सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है। देश में सोडियम नाइट्राइड के तीन अन्य उत्पादक भी है।

| क्र.सं. | विवरण | यूनिट | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------|------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | दीपक नाइट्राइट लिमिटेड | मी.टन | 29,236 | 30,473 | 30,105 | 29,661 |
| 2 | अन्य उत्पादक | मी.टन | 3,955 | 4,127 | 4,500 | 4,500 |
| 3 | कुल भारतीय उत्पादन | मी.टन | 33,190 | 34,599 | 34,605 | 34,161 |
| 4 | याचिकाकर्ता का हिस्सा | % | 88.09% | 88.07% | 87.00% | 86.83% |

ग. इस उत्पाद का चीन जन गण. और यूरोपियन यूनियन सहित कई देशों से निर्यात किया जा रहा है।

| क्र.सं. | देश | आयात मात्रा मी.टन में | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | | | |
| 1 | चीन जन गण | 11,473 | 6,765 | 9,327 | 17,856 | | | |
| 2 | ईयू | 2,597 | 5,762 | 4,530 | 3,277 | | | |
| 3 | अन्य देश | 220 | 388 | 1,052 | 1,029 | | | |
| | कुल | 14,290 | 12,915 | 14,909 | 22,162 | | | |

- घ. याचिकाकर्ता ने डीजीसी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान समग्र रुप से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आयातों में अभी हाल ही में, अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। हालांकि आयातों में संपूर्ण अवधि में वृद्धि हुई है, परंतु वर्ष 2011-12 से आयातों में भारी उद्रेक आया है।
- ड. भारतीय बाजार में आयातों के बाजार हिस्से में अभी हाल ही की अवधि में तेजी से एवं भारी वृद्धि हुई है। च. आयातों में वृद्धि के कारण:
 - i) निर्यातक राष्ट्रों के उत्पादकों, खासकर चीन के उत्पादकों, के पास भारी उत्पादन क्षमता है परंतु उनकी घरेलू मांग में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरुप बेशी क्षमता का सृजन हुआ जो भारतीय घरेलू मांग को आसानी से पूरा कर सकती है।
 - ii) भारत में बढ़ती मांग के कारण, भारतीय बाजार उनका निर्यात लक्ष्य बन गया। यद्यपि संगत अविध के दौरान चीन द्वारा अन्य देशों को की गई निर्यात की मात्रा स्थिर बनी रही, वहीं भारत को निर्यातों में तेजी से एवं भारी वृद्धि हुई।

- iii) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि की गई, वहीं वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात अत्यधिक हाल के समय में इसमें गिरावट आई।
- छ. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती
 - i) क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है।
 - ii) उत्पादन और बिक्री में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात उसमें गिरावट आई। मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने भी उसी पद्धति का अनुसरण किया, जबिक आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई। सम्वर्धित आयातों, और वह भी कम कीमत पर, की उपलब्धता के कारण क्षति अविध में मालसूची में वृद्धि हुई।
 - iii) आयातों की उतराई कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है। आयात घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं। संवर्धित आयातों की मौजूदगी, और वह भी कम कीमतों पर, ने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि की तुलना में अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित कर दिया है जिससे उद्योग को भारी कीमत निग्रहण हुआ। रक्षोपाय शुल्क का उद्ग्रहण न किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के पास घाटे पर अपनी बिक्री जारी रखने अथवा अपना उत्पादन बंद करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था।

| विवरण | इकाई | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| बिक्री लागत (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 100.00 | 99.95 | 134.58 | 161.77 |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | | | | | |
| कीमत(अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 100.00 | 104.43 | 115.56 | 119.87 |
| सी आई एफ (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 100.00 | 110.32 | 112.44 | 121.98 |

- iv) आयात घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक रहे हैं। वर्ष 2010-11 से क्षमता उपयोग में कमी आई है।
- v) रोजगार स्तर में वर्ष 2010-11 में गिरावट आई, परंतु उसके पश्चात स्थिर बना रहा। क्षति अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि हुई परंतु अभिनवतम अवधि में उसमें गिरावट आई। उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन के अनुरुप ही सुधार हुआ।
- vi) प्रति यूनिट लाभ/हानि, लाभ/हानि, पीबीआईटी, नकद लाभ तथा निवेश पर अर्जन में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई, परंतु इसके पश्चात इसमें गिरावट आ गई, जांच की अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट प्रदर्शित हुई है। घरेलू उद्योग को मौजूदा अवधि में भारी घाटा सहन करना पड़ रहा है।
- ज. निम्नलिखित तथ्यों के कारण भी गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है:
 - i) आयातों का भारतीय बाजार में भारी मात्रा में समग्र रुप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में भारी मात्रा में प्रवेश हो रहा है।
 - ii) निर्यातक देशों में निर्यातकों की इस सम्बद्ध वस्तु की भारी उत्पादन क्षमता तथा उनकी निर्यातोन्मुखता और भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए ऐसी उम्मीद है कि आयातों में और अधिक वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की संभावना है।
 - iii) घरेलू और आयातित उत्पाद में कीमत अंतर बहुत अधिक है। इस प्रकार, आयात लुभावने बने हुए हैं।
 - iv) सकारात्मक कीमत अधोरदन से घरेलू उद्योग के संवर्धित आयातों के संभावित विपरीत कीमत प्रभाव का संकेत मिलता है। इस उत्पाद की घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत पर विचार करते हुए यह कीमत अधोरदन काफी सकारात्मक है।
 - v) घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता, नकद लाभ तथा निवेश पर अर्जन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई तथा अभिनवतम अवधि में यह नकारात्मक स्तर तक पहुंच गया।

- झ. क्षति/कारणात्मक संबंधों के अन्य कारक
 - i) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरुप, आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
 - ii) कारित किया जा रहा कीमत अधोरदन घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित कर रहा है।
 - iii) पाटित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभाव ने घरेलू उद्योग को अभी हाल ही की अवधि में भारी नुकसान पहुंचाया है।
 - iv) लाभ, लगाई गई पूंजी पर अर्जन तथा नकद लाभ में कमी पर सम्वर्धित आयातों का सीधा प्रभाव हुआ है।
 - v) आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और इसमें परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग भारत में इस विचाराधीन उत्पादन की खपत में वृद्धि की दर के अनुरुप अपने उत्पादन और बिक्री में विद्धि करने में अक्षम रही है।
 - vi) कीमत एवं मात्रा से संबंधित कई आर्थिक पैरामीटरों के कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।
- ञ. याचिकाकर्ता की समायोजन, योजना लागत में कमी, मौजूदा उत्पादन क्षमता का संवर्धित उपयोग तथा क्षमता विस्तार पर प्रकाश डालता है। याचिकाकर्ता ने एक अन्य विनिर्माण सुविधा की स्थापना की है जिसमें कम्पनी का विचाराधीन उत्पाद का 18150 मी.टन उत्पादन करने का इरादा है। इस संयंत्र ने परीक्षण तौर पर नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में उत्पादन शुरु किया था परंतु संवर्धित आयातों के कारण यह अपना वाणिज्यिक उत्पादन करने में अक्षम रहा जिससे इसे भारी क्षति हुई। यह विस्तारित क्षमता सोडियम नाइट्राइट की मौजूदा तथा भविष्य में होने वाली मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, इस विस्तार से कंपनी, आयातों से होने वाली उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम होगी।

V हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की महानिदेशक द्वारा जांच

- 20. इस मामले में जांच की शुरुआत के पश्चात् (क्योंकि सुनवाई के पश्चात् किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरणों के जरिए उठाई गई आशंकाओं का, संक्षिप्तता के उद्देश्य से, निपटारा संक्षेप में किया गया, जो निम्नवत है:
 - यूरोपियन यूनियन ने यह मुद्दा उठाया है कि वर्तमान जांच केवल चीन के विरुद्ध की जानी चाहिए। केवल चीन विशिष्ट रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1995 की धारा 8ग और सीमाशुल्क प्रशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के अंतर्गत किया जा सकता है। इनका अधिनियमन चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकोल की धारा 16 के अनुसरण में किया गया है जिसमें चीन से आयातों के बारे में परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र की अनुमति है। उक्त परिग्रहण प्रोटोकोल का पैराग्राफ 16.9 यह स्पष्ट करता है कि धारा 16 का अनुप्रयोग परिग्रहण की तारीख से बारह वर्ष के पश्चात् अर्थात 11 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में जांच की अवधि के दौरान आयातों की प्रमात्रा की जांच की गई और, जैसा कि अधोलिखित तालिका से संकेत मिलता है, यह पाया गया कि जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों का अधिकांश भाग ईयू और चीन जन गण का रहा है। अतः, यह प्रतीत होता है कि यह याचिका सामान्य रक्षोपाय शुल्क नियमावली के अंतर्गत दायर की गई है और इस जांच का आयोजन भी उसी के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सामान्य रक्षोपाय जांच में सभी देशो से आयातों, विकासशील राष्ट्रो को छोड़कर, की जांच गैर विभेदकारी आधार पर की जाती है, जहां, यह जांच की जाती है कि क्या आयात न्यूनतम स्तर से अधिक पर प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। यह रिकार्ड में है कि अत्यधिक हाल की अवधि (वर्ष 2012-13) के दौरान कुल आयातों का लगभग 16 प्रतिशत आयात यूरोपियन यूनियन से हुआ है और शेष आयात चीन जन गण तथा अन्य देशों से हुआ है। अतः, इस संबंध में यूरोपियन यूनियन का तर्क तथ्यों द्वारा प्रामाणिक नहीं है और इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यूरोपियन यूनियन से भारत में सोडियम नाइट्राइट के आयात

| क्र. सं. | ईयू के सदस्य राष्ट्र | आयात र्क | ो मात्रा(मी | ∵टन) | | कुल आयात में हिस्सा (%) | | | |
|-------------|-------------------------|----------|-------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | बेल्लिजयम | - | 40 | - | _ | - | 0.31 | - | - |
| 2 | बल्गारिया | - | - | 48 | 96 | - | _ | 0.32 | 0.43 |
| 3 | चेक गणराज्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | फिनलैंड | - | 25 | - | _ | - | 0.19 | _ | - |
| 5 | जर्मनी | 2,577 | 5,659 | 4,175 | 3,529 | 18.03 | 43.82 | 28.01 | 15.92 |
| 6 | यूनान | - | - | 50 | _ | - | _ | 0.34 | - |
| 7 | नीदरलैंड्स | 20 | 38 | 84 | _ | 0.14 | 0.29 | 0.56 | - |
| 8 | स्पेन | - | - | 121 | _ | - | _ | 0.81 | _ |
| 9 | स्वीडन | _ | 25 | - | _ | - | 0.19 | _ | _ |
| 10 | यूके | _ | 25 | 100 | _ | - | 0.19 | 0.67 | _ |
| | कुल | 2,597 | 5,812 | 4,578 | 3,625 | 18 | 45 | 31 | 16 |

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

- ii) इस संदर्भ में सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 13 का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो निम्नवत है:
 - ''नियम 10 या नियम 12 के अंतर्गत अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क गैर-विभेदकारी आधार पर होगा और यह ऐसी मदों के सभी आयातों पर, इसकी स्रोत पर विचार किए बिना, लागू होगा''
- अत:, इस मामले में रक्षोपाय जांच का आयोजन लागू विधि के अनुरुप किया गया ओर इसलिए, यूरोपियन यूनियन का उपर्युक्त तर्क प्रतिधार्य नहीं है।
- iii) यूरोपियन यूनियन के इस तर्क के संबंध में कि आयात चीन से किए गए और वे ही घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे है, जबकि यूरोप से किए गए आयातों से क्षति नहीं हो रही है, याचिकाकर्ता निम्नलिखित प्रस्तृतिकरण करते हैं-
- क. अधोलिखित तालिका वर्तमान अविध में यूरोप और चीन से आयातों की मात्रा और आयात कीमत दर्शाती है। वर्ष 2009-10 में आयातों की मात्रा और कीमत को 100 (अनुक्रमिक) के रूप में विचारते हुए आयात की मात्रा एवं आयात कीमत निम्नलिखित है:-

| अवधि | आयात मात्रा(मी.टन) | | आयात की कीमत(रुपये/मी.टन) | | कीमत की प्रव | ाित |
|---------|--------------------|-------|---------------------------|-------|--------------|-----|
| | यूरोप | चीन | यूरोप | चीन | यूरोप | चीन |
| 2009-10 | 2597 | 11473 | 25864 | 22938 | 100 | 89 |
| 2010-11 | 5812 | 5765 | 25406 | 30865 | 98 | 119 |
| 2011-12 | 4578 | 9327 | 27306 | 25936 | 106 | 100 |
| 2012-13 | 3624 | 18536 | 32179 | 27117 | 124 | 105 |

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

ख. यह देखा जा सकता है कि

- वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच जहां यूरोप से आयात कीमत में गिरावट आई वही चीन से आयात कीमत में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरुप, यूरोप से आयातों में वृद्धि हुई, वहीं चीन से आयातों में गिरावट आई।
- वर्ष 2010-11 और 2011-12 के बीच यूरोप से आयात कीमतों में वृद्धि हुई वहीं चीन की आयात कीमतों में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरुप, यूरोप से आयात मात्रा में गिरावट आई, वहीं चीन से आयातों में बढ़ोत्तरी हुई।
- वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच यद्यपि यूरोप और चीन दोनों की ही आयात कीमतों में वृद्धि हुई, परंतु यूरोप से होने वाली आयात कीमतों में वृद्धि (18%) चीन से होने वाली आयात कीमतों में वृद्धि (5% से कम) से बहुत अधिक थी। इसके परिणामस्वरुप, जहां एक ओर यूरोप से होने वाले आयातों की मात्रा में गिरावट आई वहीं चीन से होने वाले आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई।
- iv) अत: यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि के दौरान चीन और यूरोप से आयातों में, इन देशों में संगत कीमत उतार-चढ़ाव के आधार पर, प्रतिस्पर्धा हो रही थी और वर्ष 2012-13 में विचाराधीन उत्पाद के भारत को हुए कुल आयातों में यूरोप से होने वाले आयातों का भारी अनुपात (लगभग 16%) है। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2012-13 में यूरोप से आयातों की मात्रा बहुत अधिक थी।
- v) किंगडम आफ सऊदी अरेबिया के तर्क के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हाल की अविध में हुए कुल आयातों में उनका हिस्सा न्यूनतम स्तर से कम है। इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक प्रभारित नहीं करना चाहिए और कटौती की स्थिति सृजित नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आशंका रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में एक अन्य संयंत्र स्थापित किया है और यह कि जांच की अविध में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि आयातित वस्तु के सीआईएफ मूल्य में हुई वृद्धि से कम है जैसा कि इससे पहले के पैराग्राफ 19(छ) (iii) में दर्शाया गया है।
- vi) जहां तक हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क का संबंध है कि आंकड़े वर्ष 2012-13 के 9 माह के लिए हैं और उन्हें वार्षिकीकृत आधार पर लिया गया है। यह उत्पादित किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने, उत्तरवर्ती रूप से, सार्वजनिक सुनवाई से ठीक पहले और सुनवाई के पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में, वर्ष 2012-13 के संपूर्ण वर्ष के लिए आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनसे आयातों में उद्रेक प्रदर्शित होता है।
- vii) कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग के पास अधिक (बेशी) क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के पास बेशी क्षमता है, पूर्णत: असंगत है। पुन: यह तर्क दिया जाता है कि चालू अविध (2012-13) के दौरान सभी देशों से आयात की कुल मात्रा 22,162 मी. टन है, जबिक मांग 49241 मी. टन की थी। घरेलू उद्योग की संवर्धित क्षमता 41,124 मी. टन है। अत:, वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 की सर्वाधिक हाल की अविध में आयातों में बढ़ने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आयातों में बढ़ोत्तरी होने की चुनौती लगातार बनी हुई है और मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की संवर्धित क्षमताएं देश में कुल मांग से अधिक नहीं है।
- viii) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि जहां पाटनरोधी शुल्क पहले से ही प्रभावी है वहां भी समानान्तर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की वांछनीयता उत्पन्न हो सकती है। इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया। यह एक तथ्य है कि पाटित आयातों के दुरुप्रभावों का प्रशुल्क अवरोध के माध्यम से सामना करने और उन्हें निष्क्रिय बनाने के लिए पाटनरोधी शुल्क अंतर्राष्ट्रीय रुप से स्वीकृत और विधिक रूप से संघारणीय एक व्यापार उपचार है। रक्षोपाय शुल्क इन प्रशुल्क अवरोधों को बढ़ाकर संवर्धित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से घरेलू उद्योग की रक्षा करने का एक उपाय है। दोनों ही शुल्कों का एक कामन कार्य होता है अर्थात् अन्य वर्षों के अतिरिक्त, आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को निष्क्रिय करना। घरेलू उद्योग वर्तमान आवेदनपत्र दायर करने के लिए विधिक रूप से औचित्यपूर्ण है। डब्ल्यूटीओ

विधियां भी इसकी अनुमित प्रदान करती हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का कोई मामला नहीं उठाया है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क विभिन्न जांच अविधयों पर आधारित था, परंतु वर्तमान रक्षोपाय शुल्क का प्रस्ताव अत्यधिक अभिनवतम अविध के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसलिए एक ही क्षति के लिए दोहरा संरक्षण प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वर्तमान जांच संभावित क्षति मात्रा से संबंधित है।

- ix) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि स्वयं याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2012-13 में आयातों में वृद्धि होने और वित्तीय स्थिति में गिरावट आने, जो वित्त वर्ष 2010-2011 से प्रारंभ हुई, के बीच कोई संबंध नहीं है, इस बारे में यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू को गंभीर क्षित के बीच स्पष्ट संबंध सिद्ध करते है। सोडियम नाईट्राइट के आयातों की मात्रा में वर्ष 2010-11 में कमी आई, परंतु उसके पश्चात वर्ष 2011-12 में इसमें वृद्धि हुई और वर्ष 2012-13 में इनमें भारी एवं अत्यधिक वृद्धि हुई। आयातों में भारी बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने भी समान प्रवृत्ति का अनुकरण किया, अधिकांश पैरामीटरों में वर्ष 2011-12 और 2012-13 में इसमें गिरावट आई तद्द्वारा घरेलू उद्योग गंभीर क्षित सहन कर रहा है।
- प्र) यह मुद्दा कि घरेलू उद्योग अपनी एकाधिकारिता सृजन करना चाहता है, सही नहीं पाया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के अलावा इस उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं और वस्तुत: उत्पादकों में से एक उत्पादक अर्थात मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड (जिसे पहले मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के नाम से जाना जाता था) चंडीगढ़ ने वर्तमान याचिका का समर्थन भी किया जो रिकार्ड में उपलब्ध है।
- xi) हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। यह नोट किया जाता है कि कम कीमतों पर संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत की वृद्धि के दर के अनुरुप अपना उत्पादन तथा अपनी बिक्री बढ़ाने में अक्षम रहा। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की कुल अखिल भारतीय क्षमता भारत में कुल घरेलू मांग को परा करने के लिए पर्याप्त है।
- xii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि घरेलू और आयातित माल के तकनीकी विनिर्देशनों में अंतर है। चीन के उत्पादों में नम अंतर्वस्तु अधिक है। जहां एक ओर घरेलू उत्पाद में अधिकतम 1% नमी होती है, वहीं चीन के उत्पादों में अधिकतम 1.4% नमी होती है। शुष्क आधार अंतर्वस्तु, परिशुद्धता, लोहा और जल में अघुलनशील अंतवस्तुओं में भी अंतर होता है। तथापि, इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई थी। घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत किसी भी सूचना के अभाव में और इस तथ्य पर विचार करते हुए आयातित और घरेलू से उत्पादित उत्पाद दोनो ही समान उत्पाद अर्थात् सोडियम नाइट्राइट है, यह धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम नाइट्राइट आयातित विचाराधीन उत्पाद के सभी पहलुओं के बारे में समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के दायरे के अंतर्गत आता है और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम नाइट्राइट रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 2 (इ.) के अंतर्गत आयातित सोडियम नाइट्राइट के समान वस्तु है।

VI. महानिदेशक के निष्कर्ष

- 21. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले के रिकार्ड, घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातिकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर किए गए उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस जांच में उपयुक्त स्थानों पर निपटारा किया गया है।
- 22. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का उल्लेख है। इस अधिनियम की उप-धारा (1) में किसी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रावधान है

- जिसका भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो रही हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।
- 23. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है।
- 24. यह जांच उक्त नियमों के अनुरुप की गई है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना के जरिए रिकार्ड किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

इस मामले में विचाराधीन उत्पाद (जिसे एतद्पश्चात विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) सोडियम नाइट्राइट 25. (एनएएनओ₂) है जो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अध्याय 28 के सीमाशुल्क शीर्षक संख्या 28341010 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि,यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। सोडियम नाइट्राइट एक जारणकर्ता एवं प्रह्रासन एजेंट है। यह सफेद रंग क्रिस्टलीकृत पावडर होता है जिसका प्रयोग अधिकांशत: फार्मास्यटिकल उद्योग में, पैरासिटामाल, एनालजीन, थायोफाइलीन, केफीन का उत्पादन करने रंजक उद्योग, लुब्रिकैन्ट्स उद्योग, रबड़ उद्योग विनिर्माण, रबड़ ब्लोइंग एजेंट, ताप अंतरण लवणों और मांस प्रसंस्करण उद्योग एवं वस्त्र उद्योग में किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का उत्पादन करने में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कच्चा माल अमोनिया होता है जिसे उपयक्त कैटालिस्ट की मौजूदगी में उच्च ताप पर नाइट्स आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी पक्षकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। अत: यह सम्पृष्टि की जाती है कि विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 28341010 के अंतर्गत आने वाला ''सोडियम नाइटाइट'' है। इसके अतिरिक्त, यह भी धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम नाइट्राइट, आयातित विचाराधीन उत्पाद के सभी तरह से संभावित या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी दायरे में आता है और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम नाइट्राइट सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली. 1997 के नियम 2 (इ.) के आशय के अंतर्गत आयातित सोडियम नाइट्राइड के बिल्कुल समान वस्तु है।

ख. घरेलू उद्योग (डी आई)

- 26. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6) (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है-
 - "(ख) ''घरेलू उद्योग" का आशय
 - (i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादनकर्ताओं; अथवा
 - (ii) उन उत्पादनकर्ताओं से है जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
- 27. यह आवेदन पत्र मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, पुणे-41006 द्वारा दायर किया गया है जो सोडियम नाइट्राइट का एक बड़ा घरेलू उत्पादक (जिसे एतद्पश्चपात डी आई कहा गया है) है। इस मामले के रिकार्ड के अनुसार इस उत्पाद के निम्नलिखित तीन अन्य उत्पादक भी है अर्थात पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड, चंडीगढ़(यूटी), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उत्तर प्रदेश) और राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुम्बई (महाराष्ट्र)।
- 28. जांच की शुरुआत के पश्चात् मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड, चंडीगढ़ (जिसे पहले पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने अपने दिनांक 9 अगस्त, 2013 के एक पत्र के तहत मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनपत्र का समर्थन किया और वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए अपने उत्पादन और बिक्री की जानकारी प्रस्तुत की है। यह पाया जाता है कि रक्षोपाय जांच में समर्थक की कोई संकल्पना नहीं है। अत:, उन्हें प्रश्नाधीन जांच में घरेलू उद्योग के रूप में नही माना जाता है। तथापि, इस मुद्दे से तत्परता से संगत होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों

को क्षिति विश्लेषण के लिए रिकार्ड में ले लिया गया है। भारत में इस उत्पाद के कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के उत्पादन का हिस्सा पिछले तीन वर्षों से 88 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच परिवर्तित होता रहा है जिसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:-

| अवधि | घरेलू उद्योग का | समर्थनकर्ता सहित | कुल भारतीय | भारतीय उत्पादन में |
|---------|-----------------|-------------------|------------|------------------------|
| | उत्पादन (मी.टन) | अन्यों का उत्पादन | उत्पादन | घरेलू उद्योग का हिस्सा |
| | | (मी.टन) | (मी. टन) | |
| 2009-10 | 29236 | 3955 | 33191 | 88.09% |
| 2010-11 | 30473 | 4529 | 35002 | 87.06% |
| 2011-12 | 30105 | 4660 | 34765 | 86.60% |
| 2012-13 | 29661 | 5080 | 34741 | 85.38% |

29. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आवेदक का हिस्सा भारत में सोडियम नाइट्राइट के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ताओं को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के विरुद्ध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। अत:, यह धारित किया जाता है कि आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग बनते हैं और वे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) (6)(ख) (ii) के अंतर्गत परिभाषित और अपेक्षित आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग. सूचना का स्रोत:

- इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के 30. अध्याय 28 के सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 2834.1010 के अंतर्गत किया जाता है। इस रक्षोपाय जांच की शुरुआत डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता से दिसम्बर, 2012 तक के लिए प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर की गई। जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक के आयात आंकडे भी डीजीसीआईएंडएसएंडएस कोलकाता से प्राप्त किये गये हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित दिसम्बर, 2013 तक के आंकड़ों की जांच इस निदेशालय द्वारा मार्च, 2013 माह के लिए याचिकाकर्ता के केन्द्रीय उत्पाद कर के रिकार्डों के आधार पर यथासंभव सीमा तक की गई है। आवेदनकर्ता द्वारा यथाप्रस्तृत विधिवत सत्यापित उत्पाद कर रिकार्डों के अनुरुप विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के बारे में मार्च, 2013 तक के आंकड़ों को केन्द्रीय उत्पाद कर रिकार्डों के अनुसार क्षति विश्लेषण के लिए वार्षिक रूप से वर्ष 2012-13 के लिए समेकित आधार पर पहुंचने के लिए किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा तीन वर्षों अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए आंकड़े दिनांक 6.9.1997 के व्यापार नोटिस सं एसजी/टीएन/1/97 के तहत रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 5(2) के अंतर्गत महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा निर्धारित स्वरुप और ढंग में प्रदान कराए गए हैं। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सभी संबंधितों के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रद लागत/सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित लागत आंकड़े तथा क्षति मार्जिन का परिकलन प्रदान कराया है।
- 31. यह भी नोटिस किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो विचार किए गए आयात आंकड़ों में कोई आपत्ति की है और न ही भारत को सोडियम नाइट्राइट के सकल आयातों को संबंध में कोई सूचना प्रदान कराई है अथवा याचिकाकर्ता/डी आई द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विरोध भी नहीं किया।

घ. जांच की अवधि (पी ओ आई)

32. ''जांच की अवधि'' या रक्षोपाय जांच के लिए विचार किए जाने हेतु न्यूनतम अवधि को न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में ही और न सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में जांच की अवधि का चयन करने के लिए कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं है। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे को कोरिया के विरुद्ध यूएस-लाइन पाइप मामले में पैनल ने अपने निष्कर्ष में विस्तार से निपटारा किया है। इस मामले में पैनल ने यह रेखित किया कि यह आयातकर्ता सदस्य के जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह निश्चय करे कि "जांच की अवधि की दीर्घता" तथा उनके "विभज्जन" की अवधि क्या होगी:

''हम नोट करते है कि इस करार में इस तथ्य की कोई अपेक्षा नही है कि एक रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लम्बी होनी चाहिए और न ही यह अपेक्षा है कि क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ इस अवधि का विभज्जन कैसे होना चाहिए। इस प्रकार जांच की अवधि तथा इसके विभज्जन को जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चयनित अवधि पांच वर्ष छह माह थी, यह अवधि अर्जेन्टीना के जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अर्जेन्टीना-फुटवियर रक्षोपाय में प्रयोग की गई अवधि के बराबर है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने, अपने जांच परिणाम में, जांच की अवधि की दीर्घता के प्रश्न पर तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया, उन्होंने अवधि की दीर्घता पर परस्पर बल न देकर इस बात पर बल दिया कि जांच की अवधि के दौरान की प्रवृत्तियां पर अधिक बल न देते हुए अभिनव आयातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। लाइन पाइप जांच के मामले में आईटीसी ने केवल अंतिम बिन्दुओं की ही तुलना नहीं की अथवा जांच की संपूर्ण अवधि में समग्र प्रवृत्तियों की ही जांच नहीं की (जैसा कि अजेन्टीना ने अर्जेन्टीना -फुटवीयर रक्षोपाय मामले में जांच में किया था)। इसने आयात के संबंध में आंकड़ों विश्लेषण पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया था/और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि जांच के लिए एक ऐसी अवधि का चयन करके, जो 5 वर्षों और छह माह की अवधि तक फैली हो, आईटीसी ने अनुच्छेद-XIX और अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है: प्रथम, करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम अंतर्निष्ट नही है जो जांच की अवधि की दीर्घता से संबंधित हो; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयन की गई अवधि इसे अभिनव आयातों पर प्रकाश डालने की अनुमति देती हैं; तृतीय आईटीसी द्वारा चयन की गई अवधि पर्याप्तत: काफी लम्बी है जो बढ़े हुए आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने की अनुमति प्रदान करती है। (पैरा 7.196, 7.199 और

33. पैनल ने उसी यू एस-लाइन पाइप मामले में उल्लेख किया कि:

"एक रक्षोपाय जांच में संवर्धित आयातों की जांच करने के लिए जांच की अविध वही रहती है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित की जांच करने के लिए रहती है। यह पाटनरोधी या प्रतिवलनकारी शुल्क जांच की स्थिति में एक दूसरे से अलग-अलग रहती है जहां पाटन या इम्दादीकरण की मौजूदगी का मूल्यांकन करने की अविध सामान्यत: वास्तिवक क्षिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच की अविध से कम होती है। हमारा विचार है कि इस अंतर के पीछे एक मुख्य कारण जैसा कि अर्जेन्टीना-फुटवियर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने पाया, यह है कि ''यह निर्धारण करना कि क्या 'इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में आयातों की जरुरत को पूरा कर लिया गया, केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है।" अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जब संवर्धित आयातों का निर्धारण करने का मामला आता है तो ''सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अविध के लिए आयातों की प्रवृत्ति पर विचार करना अपेक्षित होता है"। आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन केवल एक निश्चित समयाविध के लिए किया जा सकता है। अत:, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वह विचार, जो अपीलीय निकाय ने क्षिति निर्धारण करने के लिए एक संगत अविध के बारे में अभिव्यक्त किया है, भी सम्वर्धित आयातों का निर्धारण करने पर लागू होते हैं। (पैरा 7.209)²

¹ डब्लू टी/डीएस 202/आर, दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइपलाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

²डब्लू टी/डीएस 202/आर, दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइपलाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

- 34. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देशों का प्रावधान न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू विधियों में किया गया और न ही रक्षोपाय करार और जीएटीटी के अनुच्छेद-XIX में किया गया है। तथापि, ऊपर उद्धृत किए गए संदर्भ की मूल भावना में ऐसा प्रतीत होता है कि संगत अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लम्बी होनी चाहिए कि इससे बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकें और यह न केवल अभिनव विगत में समाप्त होना चाहिए बल्कि जांच की अवधि ही अभिनव विगत से संबंधित हो।
- 35. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन की गई अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लम्बी होनी चाहिए कि इससे बढ़े हुए आयातों के संबंध में निष्कर्ष निकालने और ऋतुकालिक विभेदों के प्रभाव को निष्क्रिय करने की अनुमित मिल सके, वर्ष दर-वर्ष आधार पर वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 के आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरुआत के नोटिस में दिसम्बर, 2012 तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिकीकृत आधार पर विचार किया गया है। इन आयात आंकड़ों का अब मार्च, 2013 तक के लिए अद्यतनीकरण कर दिया गया है। इसलिए, इन तथ्यों पर विचार करते हुए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के आंकड़ों पर विचार करना उपयुक्त पाया गया।

ड. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

- 36. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 7 और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 में कितपय सूचना से संबंधित गोपनीयता करार के लिए प्रावधान है। नियमों में प्रावधान है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी जानकारी का वास्तविक आधार पर खुलासा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो कंपनी की गोपनीय जानकारी हो और जिसका प्रकटन उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों के गंभीर क्षित पहुंचा सकती हो और जो सार्वजिनक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजिनक रूप से खुलासा न किया हो।
- 37. घरेलू उद्योग ने कुछ जानकारी गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस सं.एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुरुप रक्षोपाय साधनों के लिए आवेदन पत्र का अगोपनीय पाठ प्रदान कराया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदनपत्र दायर करते समय गोपनीयता की मांग के लिए कारण प्रस्तुत किए हैं, जो तर्क संगत प्रतीत होते हैं और इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया गया।

च. पाटनरोधी उपाय

38. आज की तारीख के अनुसार संबंध विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क भी लगा है। यथासंशोधित, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और यथासंशोधित, सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी प्राधिकारी ने चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में अपनी वित्तीय निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 30 जून, 2011 के सं. 15/4/2010-डीजीएडी के तहत अधिसूचित किया और उस पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की सिफारिश की और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 76/2011-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। पाटनरोधी प्राधिकारी ने सोडियम नाइट्राइट के यूरोपियन यूनियन से आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच दिनांक 23 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 15/1009/2012-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की और केन्द्रीय सरकार ने अपनी दिनांक 10 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 04/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत इस शुल्क को एक अन्य वर्ष के लिए बढ़ा दिया।

छ. संवर्धित आयात

- 39. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख है और इसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

 "(1) यदि केन्द्रीय सरकार, यथायोग्य समझी गई जांच करने के पश्चात, संतुष्ट है कि भारत में किसी वस्तु का आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी है तो, वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर रक्षोपाय शल्क अधिरोपित कर सकती है"
- 40. नियमों में यह अधिदेशित किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए, आयातों में वृद्धि होना एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। अत: यह निर्धारित करना कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में इतनी अधिक मात्रा में हुई है कि उस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जरुरी हो, तो नियमों में यह विश्लेषण करने की अपेक्षा की गई है कि आयातों में यह वृद्धि संपूर्ण रूप में अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में हुई है।
- 41. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में 'संवर्धित मात्रा' को निम्नवत परिभाषित किया गया है:
 - "(ग) ''संवर्धित मात्रा'' में आयातों में वृद्धि संपूर्ण रूप में या घरेलू उद्योग के संगत रूप में हुई वृद्धि होती है।''
- 42. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी)³ में, पैनल के विपरीत, अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक मात्रा में हुई हो कि जिससे गंभीर क्षित कारित हुई हो या गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। संगत उद्धरण निम्नलिखित है:-
 - "131. यह निर्धारण कि क्या 'इन संवर्धित मात्राओं में" आयात की जरुरतें पूरी होती है, यह केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी जांच के लिए साधारण तौर पर यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं होता है कि इस उत्पाद के आयात इस वर्ष, पिछले वर्ष के आयातों से अथवा पिछले पांच वर्ष में हुए आयातों से अधिक हुए। पुन: और यह पुनरावृति जैसी प्रतीत होती है, आयातों की संवर्धित मात्रा भी पर्याप्त नहीं होगी। "ऐसी संवर्धित मात्रा" होनी चाहिए जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित की गई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी गई हो जिससे कि रक्षोपाय शुल्क लागू करने के लिए इस अपेक्षा को पूरा किया जा सके और रक्षोपाय संवंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और जीएटीटी 1944 के अनुच्छेद :1 (क) दोनों में हमारा विश्वास है कि, यह अपेक्षा की जाती है कि, आयातों में यह वृद्धि पर्याप्त, अभिनव, अचानक, तीव्र एवं भारी मात्रा में गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों रुपों में हुई हो जिससे कि "गंभीर क्षति" कारित हुई हो या 'गंभीर क्षति' की चुनौती उत्पन्न हो गयी हो।
- 43. यू एस व्हीट ग्यूटेन⁴ संबंधी पैनल ने "ऐसी मात्रा में संवर्धित" वाक्यांश की व्याख्या निम्नवत की है:
 "8.31 अनुच्छेद :1 (क) गाट, 1994 और रक्षोपाय करार '(एस ए)' अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल
 "वृद्धि" के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का उल्लेख नहीं है बिल्क उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में "वृद्धि"
 की परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रकृति के बारे में विशिष्ट जरुरतों का उल्लेख हैं, गाट 1994 के
 अनुच्छेद:1, (क) तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 दोनों में अपेक्षा की जाती है कि उस उत्पाद का
 संबंधित सदस्य के भू-भाग में आयात इतनी अधिक मात्रा में (घरेलू उत्पादन के संबंधित या समग्र रूप में)
 किया जा रहा है कि गंभीर क्षति कारित होती हो या गंभीर क्षति की चुनौती सृजित हो गयी हो। अत:,
 आयात में केवल वृद्धि काफी नहीं है। बिल्क इस अर्जेन्टीना-फुटवीयर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय के इस
 निर्णय से सहमत है कि यह वृद्धि पर्याप्त अभिनव, अचानक, तीव्र एवं परिणात्मक और गुणात्मक दोनों रुपों

³ अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी) संबंधी अपीलीय निकाय की रिपोर्ट डब्लू टी/डी एस/121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999

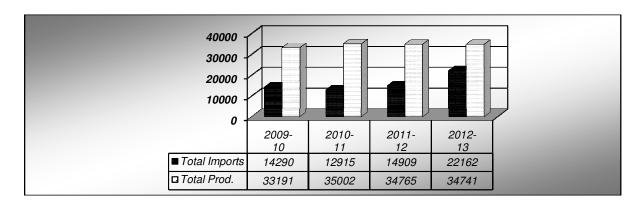
⁴यू एस हवीट ग्ल्यूटेन संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्लू टी/डीएस 166/आर 31 जुलाई, 2000

में इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे ''गंभीर क्षति'' कारित हो रही हो या उसकी चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

(क) समग्र रुप में संवर्धित आयात

44. ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में सोडियम नाइट्राइट के संवर्धित आयातों का विश्लेषण किया गया है। भारत में सोडियम नाइट्राइट का आयात कई देशों में किया जाता है और प्राथमिकत: इसका आयात चीन एवं जर्मनी से किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट के आयातों ने संपूर्ण रूप से और घरेलू उत्पादन एवं मांग की तुलना में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है जिसमें घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान नाइट्राइट के आयातों की प्रमात्रा निम्नलिखित हैं:

| वित्त वर्ष | कुल आयात (मी.टन) | अखिल भारतीय उत्पादन (मी.टन) |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 2009-10 | 14290 | 33191 |
| 2010-11 | 12915 | 35002 |
| 2011-12 | 14909 | 34765 |
| 2012-13 | 22162 | 34741 |

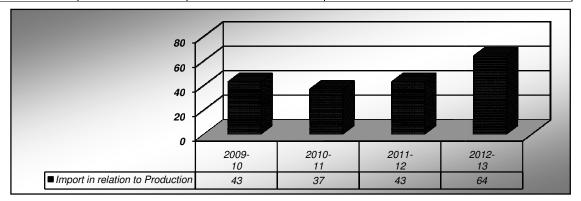


45. उपर्युक्त तालिका तथा उसके रेखाचित्रीय प्रतिनिधित्वीकरण से यह स्पष्ट है कि आयातों में संपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आयात, जो वर्ष 2009-10 में 14290 मी.टन थे, बढ़कर वर्ष 2012-13 में 22162 मी.टन हो गए, यह 55 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में लगभग 48 प्रतिशत की अचानक वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में आयातों में कमी आई, यह वह अविध है जब घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। यह देखा जाता है कि वर्ष 2010-11 में, जहां आयात कीमत में वृद्धि हुई वही आवेदनकर्ता की बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हो पायी। वर्ष 2011-12 में आवेदनकर्ता की कीमत में भारी वृद्धि हुई, उसी समय आयात कीमत में भी कुछ वृद्धि हुई। यह स्पष्टीकरण ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्ष 2009-10 के स्तर से वर्ष 2010-11 में आयातों की मात्रा में कुछ कमी और उसके पश्चात् बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा यह इंगित किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के चीन से आयातों पर लगे पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने पर, दिनांक 17/01/2006 की अधिसूचना संख्या 03/06-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की तुलना में दिनांक 22.12.2009 की अधिसूचना संख्या 143/09-सीमाशुल्क के तहत उच्चतर दर पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था और वर्ष 2010-11 में आयातों में कमी होने का शायद यही कारण था।

(ख) उत्पादन के संबंध में आयात

46. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में आधार वर्ष से तुलना करने पर घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई। कुल उत्पादन के संबंध में आयात जो 2009-10 में 43 प्रतिशत थे, वर्ष 2012-13 में 21 प्रतिशत तक बढ़ कर 64 प्रतिशत हो गए, जो एक भारी वृद्धि है।

| वित्त वर्ष | कुल आयात (मी.टन) | अखिल भारतीय उत्पादन (मी.टन) | उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत |
|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2009-10 | 14290 | 33191 | 43 % |
| 2010-11 | 12915 | 35002 | 37 % |
| 2011-12 | 14909 | 34765 | 43 % |
| 2012-13 | 22162 | 34741 | 64 % |

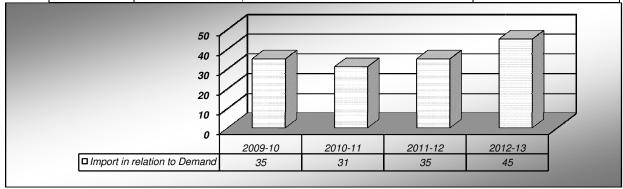


47. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन के संबंध में, दोनों रूपों में, वृद्धि हुई है और यह कि आयातों में वृद्धि में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई हैं जो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के आशय के अंतर्गत ''संवर्धित आयात'' संस्थापित करने के लिए काफी है।

ग. मांग के संबंध में आयात:

48. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद की मांग या खपत का निर्धारण विभिन्न देशों से भारत को इस उत्पाद के आयातों, घरेलू उद्योग (डी आई) की घरेलू बिक्रियों और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों के रूप में की जाती है। इस अवधि में उस तरह निर्धारित मांग/खपत में परिवर्तन की तुलना विभिन्न स्रोत से आयातों तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तियों में परिवर्तन से की गई है ताकि यह अवधारित किया जा सके कि विचाराधीन उत्पाद के भारत को आयातों में देश में इस उत्पाद की मांग या खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। निम्नलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि मांग की तुलना में आयात, जो वर्ष 2009-10 में 35 प्रतिशत थे वर्ष 2012-13 में 10 प्रतिशत तक बढ़कर 45 प्रतिशत हो गए, यह एक भारी वृद्धि है।

| वित्त वर्ष | कुल आयात (मी.टन) | ग्राही खपत सहित कुल मांग (मी.टन) | मांग की तुलना में आयातों का प्रतिशत |
|------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 2009-10 | 14290 | 41056 | 35 % |
| 2010-11 | 12915 | 41164 | 31 % |
| 2011-12 | 14909 | 42245 | 35 % |
| 2012-13 | 22162 | 49241 | 45 % |



ज. आयातों में वृद्धि/अप्रत्याशित विकास के कारण

- 49. यह नोट किया जाता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा उन अप्रत्याशित परिस्थितियों का विश्लेषण करने का कोई अभिव्यक्त दायित्व/अपेक्षा नहीं है क्योंकि क्रियापद्धित संबंधी भारतीय नियमावली में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है जिसका अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करने के लिए पालन किया जाना चाहिए अथवा नहीं रक्षोपाय संबंधी डब्लूटीओ करार में भी ऐसी किसी क्रियाविधि के संबंध में कोई निर्धारण किया गया है जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए अथवा ऐसा कोई मापदंड भी नहीं है जिसे अप्रत्याशित विकास का निर्धारण करते समय पूरा किया जाना चाहिए। तथािप, जीएटीटी के अनुच्छेद के साथ पठित रक्षोपाय करार में राष्ट्रीय प्राधिकारियों को उस ''अनपेक्षित विकास'' की जांच करने का दायित्व दिया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हे। यह स्पष्ट है कि यह निदेशालय अपनी जांच में 'अनपेक्षित विकास' के मुद्दे की लगातार जांच करता रहा है। इसलिए, यह उस अनपेक्षित विकास या उन परिस्थितियों की जांच करना महत्वपूर्ण माना जाता है जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है।
- 50. अर्जेन्टीना-फुटवियर (ई सी मामले) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि वाक्यांश 'अनपेक्षित विकास" का आशय उस विकास से होता है जो अप्रत्याशित रुप से घटित हो जाए। 'अनपेक्षित विकास" में यह अपेक्षा की जाती है कि कोई ऐसा विकास हो जिससे उस उतपाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में किया जा रहा हो और वह आयात ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिनके कारण घरेलू उत्पादकों को 'अप्रत्याशित'' गंभीर क्षति कारित हुई हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वे विकास होते हैं जो अपेक्षित न हों अथवा उनकी तब उम्मीद की जाए जब सदस्य वह उत्तरदायित्व ले लें।
 - 50.2 तब, अर्जेन्टीना-फुटवियर (ई सी) मामलों में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि 'अनपेक्षित विकास' की जरूरत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए कोई पृथक 'शर्त' स्थापित नहीं करता है परंतु यह ''परिस्थितियों'' के एक निश्चत सेट का वर्णन करता है।

- 51. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया है जिसके कारण चीन से विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयात हुए:
- (क) चीन की क्षमता में वृद्धि जिसके कारण भारत को निर्यात का व्यवर्तन हुआ: याचिकाकर्ता ने प्रस्तुतिकरण किया है कि निर्यातकर्ता देशों, खासकर चीन, में उत्पादकों ने महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं अर्जित कर ली हैं। इन देशों में मांग में कमी होने के कारण ये उत्पादक भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। भारत की सारी मांग को इन देशों से निर्यातों द्वारा पूरा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि भारत अपनी बढ़ती मांग के कारण एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। चीन और ई यू से अन्य देशों को निर्यात पूर्ववत ही बने रहे परंतु चीन और ई यू से भारत को निर्यात की मात्रा में जांच की अविध के दौरान, खासकर विगत तीन वर्षों में अप्रत्याशित विद्धि हुई है।

| वित्त वर्ष | चीन से भारत को निर्यात (मी.टन) | चीन से अन्य देशों को निर्यात (मी.टन)* |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2010-11 | 6765 | 32,834 |
| 2011-12 | 9327 | 33,812 |
| 2012-13 | 18536 | 34,789 |
| Trend | | |
| 2010-11 | 100 | 100 |
| 2011-12 | 138 | 103 |
| 2012-13 | 274 | 106 |

*स्रोत: चीन कस्टम

- ख. यूएसए द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण: इसके अतिरिक्त, यूएसए ने चीन जन.गण. तथा जर्मनी से सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर वर्ष 2008 से ही पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर रखा है। संयुक्त राज्य बाजार में व्यवसाय के अवसर समाप्त हो जाने पर चीन और जर्मनी के उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत में बढ़ती मांग के कारण इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया।
- 52. दिए गए आंकड़ों की जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन और यूरोपियन यूनियन के उत्पादक भारतीय बाजार को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं। प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों में बेशी क्षमताएं मौजूद हैं और यह पाया गया है कि सोडियम नाइट्राइट की भारतीय मांग/स्पष्ट खपत में वृद्धि हो रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि आयातों में वृद्धि के कारण क्या हैं। अत:, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत उपर्युक्त कारण अप्रत्याशित विकास हो सकते हैं।

झ. गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती

- 53. 'गंभीर क्षति'⁵ का आशय घरेलू उद्योग की स्थिति को संपूर्ण क्षति पहुंचाना; और ''गंभीर क्षति की चुनौती''⁶ का आशय है गंभीर क्षति का स्पष्ट रूप से आसन्न खतरा।
- 54. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस मूल्यांकन में क्या प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा कोई मूल्यांकन विशिष्ट मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की

⁵ सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6)(ग)

⁶ सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख)(6)(घ)

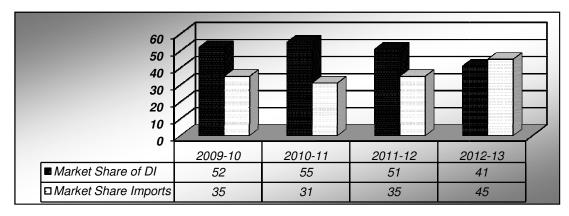
परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न मामलों में विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक अनिवार्य रूप से यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक तथ्य में "गिरावट" हो रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जो उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षयण" प्रदर्शित कर सकता है और इसलिए यह गंभीर क्षित के लिए निष्कर्ष के न्यायोचित ठहराया जा सकता है, वहीं, किसी दूसरे मामले में कितपय निश्चित कारणों में हो सकता है कि गिरावट न हो रही हो परंतु ऐसा होते हुए भी समग्र तस्वीर उद्योग का 'भारी समग्र परिक्षयण'' प्रदर्शित कर सकती है। इस प्रकार सभी सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का तकनीकी परीक्षण करने के अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि उन सभी संगत कारकों के आलोक में, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- 55. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है : ''गंभीर क्षति की चुनौती'' का आशय गंभीर क्षति के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।
- 56. सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं क्षिति निर्धारण) नियमावली के अनुबंध-1 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है: ''जांच में यह निर्धारण करने के लिए कि क्या निरुपित उद्योग को गंभीर क्षित संवर्धित आयातों से हुई अथवा संवर्धित आयात गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणनीय प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; और इसमें खासकर संबंधित वस्तु के आयातों में संपूर्ण एवं संगत रूप से दर एवं राशि में वृद्धि, बढ़े हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग में हासिल किया गया हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन के संबंध में जांच शामिल होगी।''
- 57. तद्नुसार गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करने में नियमों में उल्लिखित सभी कारकों तथा उन अन्य सभी कारकों पर विचार किया गया जो गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत है। किसी भी एक कारक को निवर्तनकारी के रूप में नहीं माना गया। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत सभी संगत कारकों तथा प्रतिस्पर्धा की शर्तों, जो पीड़ित उद्योग से संगत है, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का, उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में, मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 58. यह धारित किया जाता है कि सोडियम नाइट्राइट के बढ़े हुए आयातों ने सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादको को गंभीर क्षतिकारित की है और वे गंभीर क्षति की चुनौती कारित कर रहे हैं । यह तथ्य निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट है :
- क. **बाजार हिस्सा:** आयातों से तुलना करने पर घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। आवेदनकर्ताओं का वर्ष 2010-11 में 55 प्रतिशत बाजार हिस्सा था जो वर्ष 2011-12 के दौरान घटकर 51 प्रतिशत रह गया। आवेदनकर्ताओं के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 के दौरान और अधिक गिरावट आई तथा यह केवल 41 प्रतिशत ही रह गया। दूसरी ओर आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 35 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2012-13 में 45 प्रतिशत हो गया।

| वित्तीय वर्ष | कुल आयात (मी.टन) | घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.टन) | अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (मी.टन) | सहित कुल | बाजार हि प्रतिशत | हेस्से का | मालसूची (मी.टन) |
|-----------------|------------------------|---|---|----------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | घरेलू उद्योग | आयात | |

⁷ डब्लूटीओ की अर्जेन्टीना फुटवीयर मामला अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित

| 2009-10 | 14290 | 21526 | 3959 | 41056 | 52 | 35 | 170 |
|----------|-------|-------|------|-------|----|----|-----|
| 2010-11 | 12915 | 22673 | 4517 | 41164 | 55 | 31 | 186 |
| 2011-12 | 14909 | 21368 | 4667 | 42245 | 51 | 35 | 200 |
| 2012- 13 | 22162 | 20257 | 5047 | 49241 | 41 | 45 | 943 |
| | | | | | | | |



ख. **उत्पादन:** यद्यपि वर्ष 2009-10 की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई, फिर भी, यह वर्ष 2010-11 में 30473 मी.टन से घटकर वर्ष 2011-12 में 30105 मी.टन तथा 2012-13 में 29661 मी.टन रह गया।

| वित्त वर्ष | उत्पादन (मी.टन) |
|------------|-----------------|
| 2009-10 | 29236 |
| 2010-11 | 30473 |
| 2011-12 | 30105 |
| 2012-13 | 29661 |

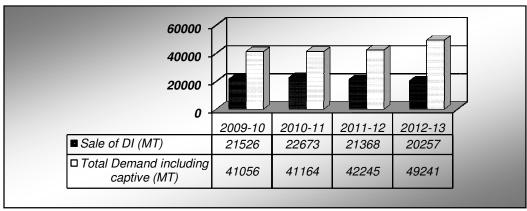
ग. **क्षमता उपयोग**: घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2010-11 में 98 प्रतिशत था अभी हाल ही की अविध में घटकर वर्ष 2012-13 में 72 प्रतिशत रह गया। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की कुल अखिल भारतीय क्षमता, भारत में कुल मांग को पूरा करने के लिए, अभी हाल ही की अविध में पर्याप्त है, परंतु इसका उपयोग 72 प्रतिशत तक कम है, निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

| वित्तीय वर्ष | घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता (मी.टन) | क्षमता उपयोग (%) | अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता (मी.टन) |
|--------------|--|------------------|---|
| 2009-10 | 31000 | 94 | 39500 |
| 2010-11 | 31000 | 98 | 39500 |
| 2011-12 | 31000 | 97 | 39500 |
| 2012-13 | 41124 | 72 | 49625 |

| 100 - 50 - | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| ■ Capacity Utilization of DI after expansion | 94 | 98 | 97 | 72 |
| ☐ Capacity utilisation of DI before exapansion | 94 | 98 | 97 | 95 |

- यह देखा जाता है कि वर्ष 2012-13 में बेशी क्षमताएं जोड़ी गई परंतु उस वर्ष वास्तविक उत्पादन की मात्रा विगत वर्ष में हुए उत्पादन की तुलना में कमी थी।
- (॥) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए कि न्यून उपयोग, संवर्धित क्षमता के कारण हुआ है और इस तथ्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2012-13 में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया था, यह जांच करना विवेकपूर्ण माना गया कि क्या क्षमता उपयोग में यह कमी क्षमता में वृद्धि के कारण आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में विस्तार नहीं किया होता तो भी वर्ष 2012-13 में इसका क्षमता उपयोग 95 प्रतिशत ही रहता जो वर्ष 2010-11 के पश्चात् क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अत: यह प्रतीत होता है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में विस्तार नहीं किया होता तब भी इसके क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति ही प्रदर्शित होती।
- (iii) जहां तक घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग का संबंध है ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग अपनी संवर्धित क्षमता के बावजूद अभी सर्वाधिक हाल ही की अविध में बढ़ते हुए आयातों के कारण न्यूनतर क्षमता उपयोग का सामना कर रहा है।
- **घ**. **बिक्रियों के स्तर पर परिवर्तन**: यद्यपि आधार वर्ष 2009-10 से तुलना करने पर घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई है तथापि इसमें गिरावट होकर यह वर्ष 2010-11 में 22673 मी.टन तथा वर्ष 2012-13 में 20257 मी.टन ही रह गयी। बिक्री में यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद आई है कि इसकी मांग, जो वर्ष 2010-2011 में 41164 मी.टन थी, बढ़कर वर्ष 2012-13 में 49241 मी.टन हो गई। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों एवं बाजार हिस्से में, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि होने के बावजूद, आयातों में उद्रेक के कारण, घाटा हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है।

| वित्त वर्ष | घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.टन) | ग्राही खपत सहित कुल मांग (मी.टन) |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2009-10 | 21526 | 41056 |
| 2010-11 | 22673 | 41164 |
| 2011-12 | 21368 | 42245 |
| 2012- 13 | 20257 | 49241 |



- **ड. रोजगार** : क्षति अवधि के दौरान रोजगार तथा उत्पादकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इस अवधि में इसने सामान्य वृद्धि प्रदर्शित की। आवेदनकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ये पैरामीटर कई अन्य पैरामीटरों पर निर्भर करते हैं और घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं।
- च. मालसूची: आयातों में वृद्धि तथा घरेलू बिक्री में कमी के कारण, घरेलू उद्योग को अपनी मालसूची का संचयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इति स्टाक जो वर्ष 2009-10 में 170 मी.टन था, से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 200 मी.टन हो गया और यह पुन: बढ़कर वर्ष 2012-13 में 943 मी.टन हो गया, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है:-

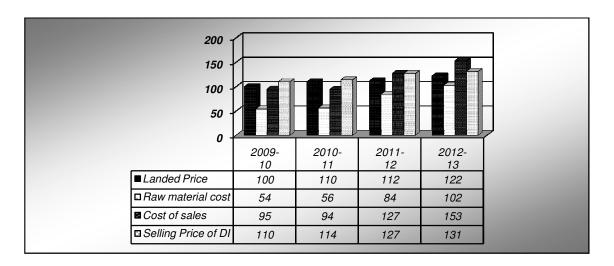
| अवधि | इति मालसूची (मी.टन में) |
|---------|-------------------------|
| 2009-10 | 170 |
| 2010-11 | 186 |
| 2011-12 | 200 |
| 2012-13 | 943 |

छ. **लाभ एवं हानि :** घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता और निवेश पर अर्जन में इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग अब वित्तीय घाटा सहन कर रहा है। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :-

| वित्तीय वर्ष | लाभप्रदायकता (रु./मी.टन) (अनुक्रमित) | निवेश पर अर्जन(%) (अनुक्रमित) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 2009-10 | 100 | 100 |
| 2010-11 | 133 | 149 |
| 2011-12 | -4 | 4 |
| 2012-13 | -144 | -102 |

ज. कीमत अधोरदन, निग्रहण/अवमंदन: यह पाया जाता है कि सोडियम नाइट्राइट की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है। घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में भारी अंतर है। आयातों की उतराई कीमत की तुलना में कच्चे माल की कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | विवरण | यूनिट | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | आयातों की उतराई कीमत | | | | | |
| ' | (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 100 | 110 | 112 | 122 |
| | कच्चे माल की लागत | | | | | |
| 2 | (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 54 | 56 | 84 | 102 |
| 3 | बिक्री लागत (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 95 | 94 | 127 | 153 |
| | घरेलू उद्योग की बिक्री | | | | | |
| 4 | कीमत (अनुक्रमित) | रुपये/मी.टन | 110 | 114 | 127 | 131 |



उपर्युक्त तालिका/रेखाचित्र से यह देखा जाता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में तेजी से वृद्धि हुई तथापि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बिक्री लागत में हुई वृद्धि की दर की तुलना में बहुत वृद्धि की दर, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि की दर की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2010-11 तक लाभ का दावा कर रहा था तथा वर्ष 2011-12 में उसे मामूली सा नुकसान हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में केवल 3.14 प्रतिशत मामूली सी वृद्धि की गई जो बिक्री लागत में हुई तीव्र वृद्धि (20.47 प्रतिशत तक) की तुलना में आयातों के उतराई मूल्य में वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार आयात बाजार में घरेलू उद्योगों की कीमतों का निग्रहण कर रहे थे। यह देखा जाता है कि अधिकांश बिक्रियों की कीमत, कच्चे माल में हुई बढ़ोतरी की दर की तुलना में बहुत कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के परिणाम स्वरूप अंतरिनविष्टि लागत में वृद्धि के अनुपात से अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोका गया जिसके कारण उसे गंभीर क्षति हुई।

ञ. गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष:

59. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई। सोडियम नाइट्राइट के आयातों की मात्रा में वर्ष 2010-11 में कमी आई परंतु उसके बाद वर्ष 2011-12 में इसमें वृद्धि हुई और वर्ष 2012-13 में इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई। आयातों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति उठानी पड़ी। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने भी आयातों का प्रवृत्ति का अनुकरण किया अर्थात अधिकांश पैरामीटरों के बारे में वर्ष 2010-11 में इसमें सुधार हुआ और उसके बाद वर्ष 2011-12 और 2012-13 में इसमें गिरावट आई।

- 60. बाजार हिस्सा, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभ/हानि, लाभ प्रदायकता, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन में वर्ष 2010-11 में सुधार हुआ परंतु इसके उपरांत वर्ष 2011-12 में इसमें गिरावट आई और वर्ष 2012-13 में इसमें और अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग की मालसूची में संपूर्ण क्षिति अविध के दौरान वृद्धि हुई और वर्ष 2012-13 के दौरान इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। संपूर्ण अविध में कीमत अधोरदन देखा गया। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें, लागत में वृद्धि के अनुरुप बढ़ाने से रोक रहे हैं।
- 61. अत:, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन, उन सभी कारकों के आलोक में, करने से जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग का भारी समग्र अपक्षयन हुआ। अत:, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी।

ट. गंभीर क्षति की चुनौती

- 62. भारत में सोडियम नाइट्राइट का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के समक्ष बढ़ते हुए आयातों और भारत में आयातों की बढ़ती मात्रा की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। आयात भारत में समग्र रुप से बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। उक्त अविध के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमता और उनकी निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए ऐसी संभावना है कि आयातों में लगातार वृद्धि होती रहेगी।
- 63. घरेलू बिक्रिओं और सोडियम नाइट्राइट के आयातों के बीच कीमत अंतर से भारतीय बाजार निर्यातों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य स्थल बन गया है। इसके परिणामस्वरुप आयातों में और अधिक वृद्धि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करेगी। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का अधोरदन हो रहा है।
- 64. लाभप्रदायकता और निवेश पर अर्जन के रूप में घरेलू उद्योग की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण न किये जाने के स्थिति में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

ठ. क्षति कारित करने वाले अथवा क्षति की चुनौती उत्पन्न करने वाले अन्य कारक

- 65. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के अनुबंध के पैरा (2) में उल्लेख है कि उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि जांच से, उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध वस्तु के संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी स्पष्ट न हो जाए और यदि संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" कारित कर रहे हैं तो उस 'गंभीर क्षति" के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- 66. इस कारण, उन अन्य संभावित कारकों की भी जांच की गई जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित संगत कारक हैं:-
- क) उत्पाद की मांग: जब समग्र मांग में वृद्धि होती है तो, यह उम्मीद की जाती है कि उसी के अनुरूप घरेलू उद्योग की बिक्री में भी बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होगी; हो सकता है कि आयात भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित करें। तथापि, इस मामले में, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जबिक आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। अत: यह स्पष्टत: देखा जा सकता है कि संवर्धित आयातों में मांग के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया।
- ख) खपत की प्रणाली में परिवर्तन: घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया जाता है कि जहां तक भारतीय बाजार का संबंध है, रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रणाली में कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ है। किसी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के इस दावे के विरोध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और, इस कारण, इसे स्वीकार कर लिया गया है।
- ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा: रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं अथवा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा ने

घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो। तथापि यह एक तथ्य है कि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किये जाने के बावजूद मात्रा क्षति हुई है।

- **ष)** निर्यात निष्पादन: आवेदनकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की अल्प मात्रा का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है। आवेदनकर्ताओं ने घरेलू प्रचालनों से संबंधित लागत निर्धारण तथा क्षति से संबंधित सूचना प्रदान कराई है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति न किये जाने का उल्लेख निर्यात जरुरत अथवा इसके विपरीत को उदधृत करते हुए नहीं किया है। अत:, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए निर्यातों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
- **ड.)** प्रौद्योगिकी में विकास: आवेदनकर्ताओं ने दावा किया है कि इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भी इसका विरोध नहीं किया है। इसीलिए प्रौद्योगिकी में विकास को इस मामले में क्षति के लिए एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 67. अत: यह नोट किया जाता है कि अन्य संभावित कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है। पाटन तथा कम कीमतों के आयात में वृद्धि के अलावा अन्य ऐसे कोई कारक नहीं है जिन्हें घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो।
- ड. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध:
- 68. कोरिया-डेयरी मामले में पैनल ने ''कारण'' का निर्धारण करने के लिए आधारभूत पहुंच का निर्धारण किया है:

"कारणात्मक संबंधों का आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की जरुरत होती है तथा यह निर्धारण करना होता है कि क्या उद्योग में विकास, जिनपर गंभीर क्षति प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया, संवर्धित आयातों के कारण हुआ है। कार्य कारण संबंधों के आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिकलनीय प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित की गई क्षति को संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई क्षति के रुप में नहीं माना गया है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने में कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि उसके घरेलू उद्योग को क्षिति बढ़ते हुए आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयात, दुग्ध पाउडर तथा कच्चे दूध का उत्पादन करने वाले, घरेलू उद्योग को क्षिति पहुंचा रहे है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात कोरियाई प्राधिकारी को अन्य कारकों द्वारा कारित क्षिति के लिए संवर्धित आयातों द्वारा कारित क्षिति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। " 8

- 69. उपर्युक्त रुप से पैरामीटरों का व्यापक मूल्यांकन यह प्रदर्शित करता है कि संवर्धित आयातों द्वारा गंभीर क्षिति पहुचाई जा रही है और गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न की जा रही है। कार्यकरण संबंध का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन सभी संगत कारकों का उद्देश्य परक एवं परिकलनीय प्रकृति का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान मामले में, इस संबंध में निम्नलिखित कारक संगत है:-
 - (i) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरुप आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है;

⁸ कोरिया-डेयरी मामले में पैनल रिपोर्ट, पैरा 7.89 से 7.90

- (ii) चूंकि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से न्यूनतर कीमत पर उपलब्ध हैं इसलिए उपभोक्तागण आयातों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग की बिक्री को नुकसान हो रहा है और उनकी मालसूची में वृद्धि हो रही है;
- (iii) कारित किया जा रहा कीमत अधोरदन घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरुप बढ़ाने से वंचित कर रहा है;
- (iv) पाटित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभावों के परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में उस सीमा तक गिरावट आयी है कि अभी हाल ही की अवधि में घरेलू उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ा है।
- (v) आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है;
- (vi) कम कीमतों पर बढ़ते आयात के कारण घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में हुई वृद्धि की दर के अनुरुप अपने उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी करने में अक्षम रहा है;
- (vii) संवर्धित आयातों के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर अर्जन सभी में गिरावट आयी है।
- 70. अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति संवर्धित आयातों के कारण कारित हुई है और यही गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती भी उत्पन्न कर रही है।

ढ. जनहित

71. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद-3 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:

"कोई भी सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग, जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद के अनुरुप सार्वजिनक किए गए और पहले से ही स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के पश्चात, कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया औचित्यपूर्ण सार्वजिनक नोटिस और सार्वजिनक सुनवाई अथवा अन्य उपयुक्त साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें तथा अपने विचार व्यक्त कर सकें, इनमें अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने का और, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आशय के विचार व्यक्त करने का मौका मिल सके कि क्या रक्षोपाय शुल्क लागू करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी तथ्य एवं विधि के सभी संगत मुद्दों के संबंध में तर्कसंगत निष्कर्षों और अपने जांच परिणामों को निर्धारित करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।"

- 72. अर्थव्यवस्था में कभी-कभार विभिन्न आर्थिक पक्षकारों के हित विभिन्न एवं परस्पर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण विभिन्न पक्षकारों को अलग-अलग ढंग से प्रभावित कर सकता है और यह प्रभाव सभी विभिन्न आर्थिक पक्षकारों के लिए हमेशा सर्वाधिक उपयुक्त हो यह भी संभव नहीं है, खासकर तब जबिक उनके हित परस्पर प्रतिस्पर्धी हो। अत: विभिन्न आर्थिक पक्षकारों समूहों के हितों का उपलब्ध सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया।
- 73. आयातों की उतराई कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं। इस कीमत अधोरदन से कीमत निग्रहण हो रहा है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से बहुत कम है। घरेलू उद्योग बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरुप बढ़ाने में अक्षम रहा है और इस कारण उसे नवीनतम अविध में भारी घाटा उठाना पड़ा है। लाभ तथा निवेश पर अर्जन में गिरावट की दर के कारण और रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण न होने के कारण घरेलू उद्योग, जैसा कि उसने दावा किया है, के पास अपना व्यवसाय बंद कर देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

0.798%

- 74. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण जन हित में होगा क्योंकि इससे न केवल घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर होगी बल्कि यह घरेलू उद्योग के गिरावट में होने वाली और अधिक क्षति को रोकेगा। जहां तक रक्षोपाय शुल्क का उपभोक्ताओं/ उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव का संबंध है, यह देखा जाता है कि सोडियम नाइट्राइट की प्राथमिकत: खपत औषध उद्योग में पैरासीटामाल, एनोलजीन, थायोफाइलिन, केफिन का उत्पादन करने; विनिर्माण रसायनों, रंजक उद्योग, लुब्रिकेन्टस, रबड़ ब्लोइंग ऐजेन्टों, ताप अंतरण लवणों, मांस प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है।
- 75. घरेलू उद्योग ने एक उदाहरण उदधृत किया है और 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का परिकलन इसके प्रासंगिक अधोगामी उत्पादों पर पड़ने का दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क के कारण उनकी कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी, यदि उसको प्रासंगिक अंतिम उत्पाद (यह विचार करते हुए की घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करेगा) पर पूर्णत: आरोपित कर दिया जाता है तो उसका प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:-

परिष्कृत उत्पादों सोडियम 20% की दर शल्क नाइटाइट का % से प्रभाव क्र.सं. सेगमेंट प्रयोग औसत प्रभाव ई=सी*20% एफ=डी*ई बी डी π 1.93% 70% 0.387% 0.271% 1 रंजक एवं पिगमेंट 2 3.45% 18% 0.691% 0.124% फार्मा 3 20.71% 5% 4.143% 0.207% रबड़ ब्लोईंग एजेंट 7% 4 14.00% 2.800% 0.196% ताप उपचार

सेक्टरवार पीयूसी खपत और परिष्कृत वस्तु की प्रतियूनिट लागत

76. घरेलू उद्योग के उपयुक्त दावे का इस जांच में हितबद्ध पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है। इस मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विरोधी प्रस्तुतिकरण/प्रत्युक्ति दायर न किये जाने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों को न्यायोचित माना गया है। घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रदर्शन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षोपाय शुल्क का संबद्ध उत्पाद के प्रयोगकर्त्ताओं के विभिन्न सेगमेंटों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि कीमतों को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है तो भी प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर उसका प्रभाव बहुत अधिक विपरीत नहीं होगा और यह कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से प्रासंगिक अंतिम उत्पाद की कीमतों में कोई भारी वृद्धि नहीं होगी।

उपभोक्ताओं पर शुल्क का भारित औसत प्रभाव

77. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण जनहित में होगा और अंतिम प्रयोक्ता के हित पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ण. समायोजन योजना

78. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2) में "आयात प्रतिस्पर्धा" से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अथवा किए जाने के लिए नियोजित प्रयासों का अथवा दोनों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। रक्षोपाय संबंधी डब्लूटीओ करार में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग केवल उसी सीमा तक कर सकता है जो गंभीर से बचने अथवा उसका समाधान निकालने के लिए आवश्यक हो और जिससे समाधान सुलभ हो सके।

- 79. निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को पुनर्गठित होने के लिए सीमित समयाविध प्रदान करना होता है जिससे कि वे आयातों से अधिक प्रभावकारी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1995 की धारा 8ख (4) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) में, यदि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहे हैं तो, इस साधन के संभावित विस्तार का निषेध किया गया है।
- 80. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने एक समायोजन योजना बनाई है जो निम्नलिखित पर प्रकाश डालती है:-
 - (i) कीमत में कटौती
 - (ii) मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का और अधिक उपयोग
 - (iii) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार
- 81. आवेदनकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपने मौजूदा स्थल पर ही नवम्बर, 2012 माह में एक अन्य विनिर्माण सुविधा की स्थापना की है जिसमें कंपनी का 18150 मी.टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने का विचार है। इस संयंत्र ने नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में अपना परीक्षण उत्पादन भी प्रारंभ किया है परंतु यह संबंधित आयातों के कारण अपना वाणिज्यिक उत्पादन करने में अक्षम रहा जिससे उसे गंभीर क्षित हुई। चूंकि बढ़ते आयातों से जांच की अविध के दौरान मौजूदा संयंत्र का क्षमता उपयोग करने पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यह निश्चय किया गया कि नए संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन करना जोखिम भरा होगा। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, आवेदनकर्ता आशा करता है कि यदि एक बार रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो इस नए संयंत्र की इष्टतम क्षमता पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो जाएगी और यह कि अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं तथा मांग में वृद्धि होने की संभावनाओं पर विचार करते हुए संवर्धित क्षमता देश में सोडियम नाइट्राइट की वर्तमान एवं संभावित भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। पुन: यह उल्लेख किया गया कि लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, संयंत्र का विस्तार कंपनी को आयातों से होने वाली उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दो वर्षों की अविध के लिए रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया है जिससे कि वह आयातों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम हो सकें।
- 82. आवेदनकर्ता द्वारा यह पुन: स्पष्ट किया गया कि उपर्युक्त समायोजन योजना के अनुसार कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में होगी और इसके साथ ही वह संबद्ध वस्तु की भारत में बढ़ती संभावित मांग को पूरा करने में भी सक्षम होगी। उपर्युक्त के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनकर्ता ने एक व्यवहार्य समायोजन योजना उपलब्ध कराई है जो सोडियम नाइट्राइट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लागत में कमी, उत्पादन क्षमताओं के इष्टतम प्रयोग पर प्रकाश डालता है।

त. विकासशील राष्ट्र

83. विकासशील राष्ट्रों से होने वाले आयातों के प्रतिशत की भी जांच की गई। चीन जन गण को छोड़ कर, जिसका वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारत में हुए कुल आयातों में से 81 प्रतिशत आयात था, अन्य विकासशील राष्ट्रों का भारत में कुल आयातों में से व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से आयात हिस्सा क्रमशः 3 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से भी कम था। अतः, चीन जन गण के अलावा अन्य विकासशील राष्ट्रों के मूल से विचाराधीन उत्पाद के होने वाले आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुरुप रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

थ. निष्कर्ष:

- 84. उपर्युक्त जांच और किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि:
- क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) सोडियम नाइट्राइट के आयातों में संपूर्ण जांच अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू उत्पादन के संबंध में तथा समग्र रूप से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। अत:, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अत्यधिक हाल ही अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी उद्रेक हुआ है जिससे कि

- गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी है। आयातों में तीव्र वृद्धि उत्पादन के संबंध में तथा कुल मांग के संबंध में भी काफी महत्वपूर्ण है।
- ख घरेलू उद्योग यह अभिव्यक्त करने में सक्षम रहा है कि विचाराधीन उत्पाद का बाजार में अप्रत्याशित विकास हुआ और यह विकास चीन जन गण (कुल आयातों का 83 प्रतिशत) तथा यूरोपियन यूनियन (कुल आयातों का 16 प्रतिशत) के संबंध में विशेष रूप से हुआ।
- ग. घरेलू उद्योग ने समग्र आर्थिक पैरामीटरों अर्थात बाजार हिस्सा, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदायकता, उत्पादन और मालसूची के रूप में गंभीर क्षित का प्रदर्शन किया है। तथापि, उत्पादन तथा मालसूची के मामले में यह क्षित निरुपाधि रूप से मामूली सी है। चूंकि बढ़ते हुए आयातों ने देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए घरेलू उद्योग को आयातों से बाजार हिस्से में घाटे के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग, देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि होने के बावजूद इसकी बिक्री में कमी आने के कारण बढ़ती मालसूची तथा बढ़ते घाटे के रूप में हुई गंभीर क्षित को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुआ है। इससे जांच की अविध के दौरान हुए आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षित के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।
- घ. यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क के रूप में 2 वर्षों की अविध के लिए संरक्षण की मांग की है और इस अविध के लिए उन्होंने एक समायोजन योजना भी प्रदान की है। इस समायोजन योजना का जांच की संपूर्ण अविध के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा न तो विरोध किया गया और न ही इसे मना किया गया और इस समायोजन योजना को औचित्यपूर्ण भी पाया गया है। घरेलू उद्योग का यह तर्क भी स्वीकार्य प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का विस्तार पहले ही कर लिया है और वे अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ मिलकर इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम हैं।
- ड. यह भी अभिलेखबद्ध है कि इस विचाराधीन उत्पाद अर्थात् सोडियम नाइट्राइट पर दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 76/2011-सीमाशुल्क के तहत (चीन जन गण से आयातों पर) और दिनांक 10 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 04/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत (यूरोपियन यूनियन से होने वाले आयातों पर) दिनांक 10 अप्रैल, 2014 तक पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा हुआ है। वर्तमान जांच के दौरान, यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग को इस विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क के रूप में संरक्षण प्राप्त है, परंतु इस संरक्षण के बावजूद भी देश में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को भारी नुकसान सहन करना पड़ा है, इस कारण उन्हें रक्षोपाय शुल्क के रूप में और अधिक संरक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है जिससे कि बढ़ते आयातों से उन्हें कारित की जा रही गंभीर क्षति और गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती से बचाया जा सके। इस प्रकार, इस बात पर विचार किए बिना कि इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगा है या नहीं, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का स्पष्ट मामला बनता है अर्थात् यह रक्षोपाय शुल्क, यदि उद्ग्रहित किया जाता है तो, पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त होगा।
- च. घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में भी समर्थ रहा है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जन-हित में होगा क्योंकि इस रक्षोपाय शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यह भी उप्पादित किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के अनुक्रम में इस पहलू का न तो कोई विरोध किया है और न ही उसे नामंजूर किया है।

द. सिफारिश

85. अत:, भारत में सोडियम नाइट्राइट के बढ़ते आयातों ने सोडियम नाइट्राइट के घरेलू उत्पादों को गंभीर क्षति पहुंचायी है और वह गंभीर क्षति पहुंचाने की चुनौती सृजित कर रहे हैं और भारत में सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 में दी गई शर्तों के अनुरुप एक वर्ष एवं तीन महीनो की अविध के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा। लगाई गई पूंजी पर औचित्यपूर्ण अर्जन की अनुमति देने के पश्चात्, घरेलू उत्पादकों द्वारा सोडियम नाइट्राइट की औसत बिक्री लागत पर विचार करते हुए, यथामूल्य, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम,

1975 की प्रथम अनुसूची के सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 28341010 के अंतर्गत आने वाले सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर 30% यथामूल्य की दर से प्रथम वर्ष के लिए एवं 28% यथामूल्य की दर से द्वितीय वर्ष (केवल तीन महीनों) के लिए रक्षोपाय शुल्क, जिसे घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा के रूप में माना गया है, का अधिरोपण करने की, एतदद्वारा, सिफारिश की जाती है।

| अवधि | रक्षोपाय शुल्क की दर |
|---------------------------------------|----------------------|
| प्रथम वर्ष | 30% यथामूल्य |
| द्वितीय वर्ष (केवल तीन महीनों के लिए) | 28% यथामूल्य |

86. चूंकि चीन जन.गण को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से आयात व्यक्तिश: एवं सामूहिक रूप से 3 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, इसलिए चीन जन.गण को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों के मूल के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

[फा. सं. डी-22011/03/2013/1494] राम तीर्थ, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Directorate General of Safeguards)

(Customs & Central Excise)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2013

Subject: Safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite - Final Findings

G.S.R. 637(E).—GSR D-22011/03/2013 dated 17/09/2013 having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

I. Procedure

- 1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as Safeguard Rules) by M/s. Deepak Nitrite Limited through their consultant M/s. TPM Solicitors & Consultants for imposition of Safeguard Duty on imports of 'Sodium Nitrite' into India to protect the domestic producers of Sodium Nitrite against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Sodium Nitrite into India.
- 2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of the said Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 17th April 2013 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
- 3. A copy of the Notice of Initiation dated 17th April 2013 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

(i) Domestic Producers

M/s. Deepak Nitrite Limited, Deepak Complex, Shastrinagar, National Games Road, Pune - 411006

- Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited, (Now known as Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd.), Chandigarh (UT) - 160022
- c. National Fertilizer Limited, A-11, Sector –24, Noida 201301 (UP)
- d. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Priyadarshni, 7th Floor, Eastern Express Highway, Sion, Mumbai (Maharashtra) - 400022

(ii) Importers

- a. Ahmedabad Chemicals, Plot no. 10/7, Phase- 1, GIDC Vatva, Ahmedabad 382445
- b. Asiatic industries, 1505, GIDC Phase 1, Naroda, Ahmedabad 382330
- c. Aries Dyechem inds., C-1/260, Phase II, GIDC, Vatva, Ahmedabad- 382445
- d. Bakul Aromatics & Chemicals Limited, Sterling Center, IVth Floor, 16/2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay- 400018
- e. B. I. Mehta, 2-B, Ganga Vihar, 94, Kazi Sayeed Street, Bombay 400003
- f. Caffil Pvt. Ltd., 52, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai 400021
- g. Dintex Dyechem Limited, S.P.House 14, Vidya Vihar Colony, Usmanpura, Ahmedabad 380013
- b. Dynamic Industries Limited, 43, 4th Floor, New York Tower, "A" Near Thaltej Cross Road, Ahmedabad 380054
- i. Enzel Chem (I) Pvt. Ltd., 159, CST Road, Kalina Satacruz (East), Mumbai 400098
- j. Farmson Pharmaceuticals, Guj. Ltd., 5th Floor, Commerce Center., Sayajigunj., Baroda 390005
- k. Indocol Chem. Ltd., Vaibhav Bldg., Near Ganga jamuna Flats, Camp. Road, Shahibag, Ahmedabad-380004.
- 1. Island Veerchemie, A-4, Cooperative Inds. Estate, Balanager, Hyderabad 500037
- m. Jansons Limited, 101, Jolly Bhavan No. 1, 10, New Marine Lines, Mumbai-400020.
- n. Ketul Chem. Pvt. Ltd., 114/115, Dattani Trade Center, Chandravarkar Road, Borivalli, (West) Mumbai 400092
- o. Metrochem Industries, 508/509, Shilp Bldg., C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009
- p. Manish Chemicals, C-1/343, Near Deverson, GIDC Odhav, Ahmedabad-382410
- q. Parsin Chemicals Limited, 6-3-347/22/B, Dwarkapuri Colony, Near Sibabad Temple, Hyderabad-500082
- r. Prabava Exports, 301, Ariean, Panjgutta, Hyderabad 500082
- s. Ravi Dyewear Co. Ltd., 121, Atlanta Nariman Point, Mumbai-400021
- t. Roha Dyechem, Suryodaya Mill Compound, M. P. Mill Road, Tardeo, Mumbai 400034
- u. Savakashi Dye O Fab, Plot # 1503, GIDC, Phase I, Naroda, Ahmedabad-382330
- v. SU Vi Chemicals Ltd., B-10, MIDC, Akklot Road, Solapur 413006

(iii) Exporters

- a. Hebei Jingxing Bureau of Mines, Fengshan Chemical Factory South Fengsha, Jingxing Mines, Shijiazhuang, Hebei Province, China.
- b. Shanxi Jiaocheng Hongxing Chemical Co., Ltd., C904 Jin gan International Commercial Center, No.91, Bing Zhou Road, Tai Yuan, Shanxi, China.
- c. Shandong Zhucheng Zhongtai Chemical Co. Ltd., No. 505 Qing ping Building, Fuguang Garden Zhucheng Shandong-262200, China.
- d. Qingdao Hengyuan Chemicals Co. Ltd. Fenghe Road 2, Jiaonan City, Shandong province, China.
- e. Fushan town Weicheng district, Weifang, Shandong, China
- f. China National & Chemicals I/E, Corp., Guizhou Yunnan, China 550001
- g. Wuhan Chemicals I/E Corp., Block 48, Wang Sang District, Hankou, Wuhan, China 430022
- Yunnan Provincial Chemicals I/E Corporate, Dong Jia Wan Bidg, Dong Feng Dang Lu, Kunming, Yunnan, China.

- i. Jiagmen Chemicals I/E Company of Guangdong China, No. 84-54, Gangkhou Road, Jiangmen, Guangdong, China
- j. Kunming Imports & Export Corp. 250, Huan Cheng Bei Road, Kunming, China
- k. China Hunan Chemicals Imp. 7 Exp. Corp. No. 41, Bayi Road (W), Changsha Hunan China-410011
- 1. Shanxi Jiaocheng Hongxing, Chemical Co., Ltd. The 14th Floor, Shuigong Building, No. 368 Qinxian North Street, Taiyuan, Shanxi, China
- m. BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Germany.
- n. Terra Nitrogen (UK) Ltd, PO Box 90 Radcliffe Crescent, Thornaby, Stockton-on-Tees, Cleveland, TS17 6BS -on-Tees Cleveland TS17 6BS

(iv) Exporting Nations:

- a. Embassy of the Republic of Korea, 9, Chandragupta Marg, Chankyapuri Extension, New Delhi.
- b. Embassy of the Federal Republic of Germany, No. 6/50G, Shanti Path, Chankyapuri, New Delhi
- c. Embassy of the People's Republic of China, 50-D, Shantipath, Chankyapuri, New Delhi.
- 4. Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users in India and other interested parties as per the information available, with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation.
- 5. Requests to consider them as interested parties were received from the following parties:
 - a. Importer: M/S Sandeep Organics Pvt. Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122 Kazi Sayeed Street, Vadgadi, Masjid(W), Mumbai-400003.
 - b. Exporting Nation/organisation: Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India, 65 Golf Links, New Delhi-110003
 - c. Exporting Nation : Ministry of Commerce and Industry, PO Box 1774, Airport Road, Riyadh-11162, Kingdom of Saudi Arabia.

All requests were accepted.

- 6. Following Interested Parties have filed the Questionnaire response:
 - a. Domestic Industry M/s Deepak Nitrite Limited,Deepak Complex, Shastrinagar, National Games Road, Pune 411006
 - b. Importer : M/S Sandeep Organics Pvt. Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122 Kazi Sayeed Street, Vadgadi, Masjid (W), Mumbai-400003
- 7. Submissions were also received from the following Interested Parties in response to the Notice of Initiation:
 - a. **Importer** M/S Enzal Chemicals India Ltd, 6/159, Mittal Indl. Estate, Sir M.V Road, Andheri (East), Mumbai-72
 - b. **Importer:** M/S Sandeep Organics Pvt. Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122 Kazi Sayeed Street, Vadgadi, Masjid (W), Mumbai-400003.
 - c. **Exporting Nation/organization**: Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India, 65 Golf Links, New Delhi-110003
 - d. **Exporter** M/S BASF SE. 67056 Ludwigshafen Germany through their Indian counterpart M/S BASF India Ltd.
- 8. Request for considering them as Interested Party was also received from the Ministry of Economy, UAE vide their letter dated 04/06/2013 but their request could not be considered as it was not received within the stipulated time. However, their submission regarding compliance of article 9.1 of the WTO Agreement on Safeguards i.e. *de-minimis* provision under the Safeguard measure in this case was taken on record. Another submission was received from Taiwan through the Taipei Economic and Cultural Center, New Delhi wherein they did not seek to be included as Interested Party but requested that article 9.1 of WTO Agreement on Safeguards, i.e., *de-minimis* provision of Safeguard measure, should be applied to them in this case.

- 9. In response to the Notice of Initiation, M/s. Punjab Chemicals and Crop. Protection Ltd. (Earlier known as M/s. Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.), Chandigarh vide their letter dated 9th August, 2013 gave their support to the Domestic Industry. They provided data regarding production, sales, and inventory of the PUC; the same was considered and taken on record for injury analysis.
- 10. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

II. Views of the Interested Parties (Post Notice of Initiation):

i. Views of Kingdom of Saudi Arabia:

11. They submitted as under:

- a. There were no exports of the product concerned from the Kingdom of Saudi Arabia to India over the last three years.
- b. No Safeguard measure should not be applied to imports of Sodium Nitrite from the Kingdom of Saudi Arabia pursuant to Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.

ii. Views of the European Union:

12. Increased Imports:

- a. The claim of significant increase in imports during 2012-2013 is based on import statistics for 9 months which have been annualized. Findings should be based on actual import volumes.
- b. Increase in imports should be attributed to China whose imports increased by 65%. Imports from other countries (Germany) had decreased during the period. India should not have initiated the investigation against all countries.

13. Injury and Casualty:

- a. The production and sales volume of the Domestic Industry remained stable over the period analysed.
- b. The capacity utilization of the petitioner has decreased between 2011-2012 and 2012-2013 because of an increase in installed capacity, from 31,000 MT to 41,000 MT. They also set up additional production capacities of more than 18,000 MT which in total was far in excess of the local demand.
- c. The objective of safeguard measures cannot be to ensure that a domestic producer would supply the totality of the domestic demand. Anyhow, in this case, as explained, the massively increased installed capacity is now significantly over the domestic demand.
- d. There is no link between increase of imports in 2012 2013 and the deterioration of the financial situation which started in the financial year of 2010 2011 according to the petitioner himself.

iii. Views of Sandeep Organics Pvt. Ltd. (Importer):

14. They submitted as under:

- a. Tthey import Chinese material only.
- b. They have imported 875 MTS from 19th March 2012 onwards.
- c. The CIF price ranges from USD 476 PMT to USD 530 PMT
- d. Imports landing costs are high due to 4% special additional duty.
- e. There is difference in technical specifications of domestic & imported material.
- f. Moisture contents are high in Chinese products. Whereas, the domestic product have maximum 1% moisture, Chinese products have maximum 1.4% moisture.
- g. There is difference in the Drybase contents, purity, iron & insoluble in water contents also.
- h. The demand is more than the supply.

- i. There is production problem in the Domestic Industry.
- j. The Domestic Industry is trying to create monopoly.
- k. There is anti dumping also.
- 1. The Domestic Industry is showing profits in share market.
- m. The consumption is very large.

iv. Views of M/s. Enzal Chemicals India Ltd. (User Industry):

- 15. They submitted as under:
 - a. They have not imported any quantity of the product under consideration for their production in the last three years.
 - b. They support imposition of import restrictions for the product which have domestic availability to save foreign exchange, but such restrictions would not create a curtailing situation by domestic manufacturers in market and the consumers were charged with higher prices than international prices.

v. Views of M/s. BASF SE, Germany (Exporter):

- 16. They submitted that following may be seen:
 - a. Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties has already initiated Sunset Review on import of Sodium Nitrite from European Union vide initiation Notification dated 23/03/2013.
 - b. Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 regarding determination of serious injury or threat of serious injury to the Domestic Industry.

III. Public Hearing:

- 17. A public hearing was held on 12th August, 2013, notice for which was sent on 25th July, 2013 to the Interested Parties. However, only the Domestic Industry i.e. M/s. Deepak Nitrite Limited and the Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India, attended the Public Hearing. No oral submissions were made by the Delegation of the European Union to India.
- 18. All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub Rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties. Interested Parties are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. In the instant Public Hearing, the Domestic Industry made oral submissions followed by a written submission whereas only one other Interested Party, namely, European Union participated, who neither made any oral submission nor filed any written submission nor any rejoinder to the written submission by the Domestic Industry. However, the written submission filed by the Domestic Industry was circulated to all Interested Parties on record but even after the expiry of the stipulated time, none of them responded. All views expressed by the Interested Parties either in the written submissions during post initiation or post hearing were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

IV. Written Submission of Domestic Industry:

- 19. The Domestic Industry submitted as follows:
- a. The product under consideration is Sodium Nitrite (NaNO₂), an oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in Pharmaceuticals industries for the production of Paracetamol, Analgin, Theophylline, Caffeine; Dye industries; Lubricants industry; Construction chemicals industry; Rubber blowing agent; Heat transfer salts, meat processing industry; Textiles, etc. The product is classified under Customs Classification CTH code 2834.1010.
- b. The production of the petitioner, M/s. Deepak Nitrite Limited, constitutes a major proportion of domestic production of sodium nitrite and hence, the petitioner constitutes Domestic Industry. There are three other producers of sodium nitrate in the country.

| S.No. | Particulars | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Deepak Nitrite Ltd. | MT | 29,236 | 30,473 | 30,105 | 29,661 |
| 2 | Other Producers | MT | 3,955 | 4,127 | 4,500 | 4,500 |
| 3 | Total Indian production | MT | 33,190 | 34,599 | 34,605 | 34,161 |
| 4 | Share of petitioner | % | 88.09% | 88.07% | 87.00% | 86.83% |

c. The product is being exported from a number of countries, including China PR and the European Union.

| S.No | Country | | Import Volu | me in MT | |
|------|-----------------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | China PR | 11,473 | 6,765 | 9,327 | 17,856 |
| 2 | EU | 2,597 | 5,762 | 4,530 | 3,277 |
| 3 | Other Countries | 220 | 388 | 1,052 | 1,029 |
| | Total | 14,290 | 12,915 | 14,909 | 22,162 |

- d. The Petitioner has relied on import data from DGCI&S. Imports have increased in the POI with respect to the base year in absolute terms and in relation to production and consumption. Further, imports have shown a recent, sudden, sharp and significant increase. While imports have been increasing over the period, there has been a surge in imports since 2011-12.
- e. The market share of imports in the Indian market has increased sharply and significantly in the recent period.
- f. Reasons for increase in imports:
 - Producers in the exporting countries, especially China, have significant production capacities but their domestic demand has declined, resulting in surplus capacities that can easily meet the Indian domestic demand.
 - ii) Due to the growing demand in India, the Indian market has become their export destination. While the volume of exports from China to other countries has remained constant over the relevant period, exports to India have increased sharply and significantly.
 - iii) Capacity utilized by the Domestic Industry for production of the product under consideration increased up to 2010-11 but declined in 2011-12 and thereafter in most recent period.
- g. Serious Injury and Threat of Serious Injury to the Domestic Industry
 - i) Demand for the product under consideration has increased significantly over the injury period.
 - ii) Production and sales increased till 2010-11 and declined thereafter. Market share in demand of the Domestic Industry also followed the same pattern, while market share of imports have increased since 2010-11. Inventories have increased over the injury period due to the availability of increased imports that are also at low prices.
 - iii) The landed price of imports is lower that the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The presence of increased imports, and at low prices, has prevented the Domestic Industry from increasing its prices in proportion to increase in costs thereby causing significant price suppression. In the event of non levy of safeguard duty, the Domestic Industry would have no choice but to continue selling at losses or suspend its production.

| Particulars | Units | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Cost of Sales (Indexed) | Rs/MT | 100.00 | 99.95 | 134.58 | 161.77 |
| Selling Price of DI (Indexed) | Rs/MT | 100.00 | 104.43 | 115.56 | 119.87 |
| CIF (Indexed) | Rs/MT | 100.00 | 110.32 | 112.44 | 121.98 |

- iv) The imports are preventing the Domestic Industry from utilizing its capacity. Capacity utilisation has decreased since 2010-11.
- v) The employment level declined in 2010-11 but remained constant thereafter. Wages have increased over the injury period but declined in the most recent period. Productivity has moved in tandem with the production of Domestic Industry.
- vi) Profit/loss per unit, profit/loss, PBIT, cash profits and return on investments have increased till 2010-11, but have declined thereafter, showing significant deterioration in the POI. The Domestic Industry is suffering huge losses in the current period.

- h. There is also a threat of serious injury on account of the following factors:
 - The imports are entering the Indian market at huge quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
 - ii) Considering the huge production capacities of the subject goods of exporters in exporting countries and their export orientation and the increasing demand for the subject goods in India, imports are likely to increase causing further serious injury to the Domestic Industry.
 - iii) The price difference between domestic and imported product is very high. Thus, the imports continue to remain lucrative.
 - iv) Positive price undercutting indicates the likely adverse price effect of increased imports on Domestic Industry. Considering the net selling price of the Domestic Industry for the product, the price undercutting is significantly positive.
 - Profitability, cash profits and return on investment of the Domestic Industry has declined over the injury period and to negative levels in the most recent period.

i. Other Factors of Injury/Casual Link

- Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly.
- ii) Price undercutting being caused is preventing the Domestic Industry from increasing its prices.
- iii) The price suppression effect of dumped imports caused the Domestic Industry to suffer huge losses in the recent period.
- iv) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of increased imports.
- v) Market share of imports increased and consequently, market share of the Domestic Industry declined. Domestic Industry is unable to increase its production and sales in tandem with the rate of increase in consumption of product under consideration in India.
- vi) The growth of the Domestic Industry became negative in terms of a number of price and volume related economic parameters.
- j. The adjustment plan of the petitioner focuses on cost reduction, increased utilization of existing production capacity, and capacity expansion. The petitioner has set up another manufacturing facility wherein the company intends to produce 18,150 MT of the product under consideration. The plant commenced trial production in Nov-Dec 2012 but was unable to commence commercial production owing to increased imports causing significant injury. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of Sodium Nitrite. Further, this expansion would enable the company to face fair competition from imports.

V. Examination by Director General on views of Interested Parties:

- 20. The apprehensions raised by the Interested Parties through their written submissions during post initiation (as no submissions by any Interested Party was made post Hearing) in the case, are dealt with, in brief, for the sake of brevity, as follows:-.
 - i) The European Union raised the issue that the present investigations should only have been conducted against China. A China-specific Safeguard measure can only be applied under Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. These have been enacted in pursuance of Section 16 of China's WTO Accession Protocol which allows for a transitional product-specific safeguard mechanism with respect to imports from China. Paragraph 16.9 of the said Accession Protocol specifies that the application of Section 16 will terminate twelve years from the date of accession, that is, on 11 December, 2013. In this regard, the quantum of import in the POI was examined and as the table below indicates, it was found that major share of imports of the PUC in India during the POI had been from EU and China PR. Therefore, it appears that the petition was filed under general safeguard rules and investigation has also been conducted in the same light. It is noted that in a General Safeguard investigation, imports from all countries are to be examined on a non-discriminatory basis, except for developing nations, where the imports, whether or not entering at above de-minimis levels are examined. It is on record that during the most recent period (2012-13), about 16% of the imports were from European Union and the remaining was from China PR and other countries. Therefore, the argument of the European Union in this regard is not substantiated by facts and thus, cannot be accepted.

Import of Sodium Nitrite in India from European Union

| S. No. | EU Member Countries | , | Volume of | Import (MT) |) | | Share in tot | al Import (%) |) |
|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|--------------|---------------|---------|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | Belgium | - | 40 | - | - | - | 0.31 | - | - |
| 2 | Bulgaria | ı | ı | 48 | 96 | - | - | 0.32 | 0.43 |
| 3 | Czech | 1 | 1 | | | | | | |
| | Republic | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Finland | i | 25 | - | - | - | 0.19 | - | - |
| 5 | Germany | 2,577 | 5,659 | 4,175 | 3,529 | 18.03 | 43.82 | 28.01 | 15.92 |
| 6 | Greece | - | 1 | 50 | - | - | - | 0.34 | - |
| 7 | Netherland | 20 | 38 | 84 | - | 0.14 | 0.29 | 0.56 | - |
| 8 | Spain | - | - | 121 | - | - | - | 0.81 | - |
| 9 | Sweden | - | 25 | - | - | - | 0.19 | - | - |
| 10 | UK | - | 25 | 100 | - | - | 0.19 | 0.67 | - |
| | TOTAL | 2,597 | 5,812 | 4,578 | 3,625 | 18 | 45 | 31 | 16 |

Source: DGCI&S

ii) In this context, it is pertinent to refer to Rule 13 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, which is as follows:-

"Any safeguard duty imposed under Rule 10 or Rule 12 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, irrespective of its Source".

Thus, the Safeguard Investigation in this case has been conducted within the ambit of laws applicable and the contention of the European Union as above is, therefore, not tenable.

- iii) With regard to the argument of the European Union that imports are from China and are causing injury to the domestic industry, while imports from Europe are not causing injury, petitioner submits as follows –
- a. The table below shows import volumes and import price from Europe and China over the present period. Trends in the import volumes and import prices considering volume and price in 2009-10 as 100 (indexed) is also shown below.

| Period | Import V | Volume (MT) | Import Pri | ce (Rs./MT) | Trend | of Price |
|---------|----------|-------------|------------|-------------|--------|----------|
| | Europe | China | Europe | China | Europe | China |
| 2009-10 | 2597 | 11473 | 25864 | 22938 | 100 | 89 |
| 2010-11 | 5812 | 5765 | 25406 | 30865 | 98 | 119 |
| 2011-12 | 4578 | 9327 | 27306 | 25936 | 106 | 100 |
| 2012-13 | 3624 | 18536 | 32179 | 27117 | 124 | 105 |

Source: DGCI&S

- b. It would be seen that -
 - Between 2009-10 and 2010-11, whereas import price from Europe declined, import price from China increased. Resultantly, whereas imports from Europe increased, imports from China declined.
 - Between 2010-11 and 2011-12, whereas import price from Europe increased, import price from China declined. Consequently, import volumes from Europe declined and that from China increased.
 - Between 2011-12 and 2012-13, even though import price from both Europe and China increased, the
 increase in import price from Europe (18%) far higher than increase in import prices from China
 (below 5%). Resultantly, whereas import volumes from Europe declined, import volumes from China
 increased significantly.
- iv) It would thus be seen that the imports from China and Europe were competing with each other over the injury period based on relative price movements in these countries and imports from Europe constitute a significant proportion (about 16%) in the total imports of the product under consideration in India in the year 2012-13. It, therefore, appears that volume of import from Europe was quite significant in 2012-13.

- v) As regards the contention of the Kingdom of Saudi Arabia, it appears that their share in total imports in the recent period is below de-minimis levels. In reference to the contention that DI should not charge more than international prices and should not create curtailing situation, it appears that the apprehension is not supported by facts on record, as the DI has recently set up another plant to cater to the rising demand and that the increase in selling price of DI over the POI is lesser than the rise in the CIF value of imported goods, as shown in chart in para 19(g)(iii) hereinbefore.
- vi) In regard to the contention of Interested Party that data is for 9 months for 2012-13 and taken on annualized basis, it is found that the DI has subsequently, just before the Public Hearing and also as part of the post Hearing written submissions, submitted import data for full year 2012-13 which shows surge in imports.
- vii) It is argued by some of the interested parties that the Domestic Industry has excessive capacities. It has been submitted by the Domestic Industry that the fact of excess capacity with the Domestic Industry is entirely irrelevant. It is further contended that volumes of imports from all countries is 22,162 MT during current period (2012-13), while demand was 49241 MT. The enhanced capacity with the Domestic Industry is 41,124 MT. Thus, in view of the rising trend of increase in imports in the most recent period of 2012-13 over 2011-12, there is a continued threat of surge in imports and to neutralise the rise in demand, the enhanced capacities of DI are not significantly higher than the demand in the country.
- viii) The DI has submitted that where there is already anti-dumping duty in force, the question of desirability of simultaneous imposition of safeguard duty may arise. The issue has been analysed. It is a fact that anti-dumping duty is also an internationally accepted and legally sustainable trade remedy measure to counter and neutralize the ill effects of dumped imports through tariff barrier. Safeguard duty is a measure to protect the Domestic Industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common, i.e., neutralizing injurious effects of imports, besides other functions. The Domestic Industry is legally justified for filing the present application. WTO laws also permit the same. No violation of either domestic or international law has been pointed out by any of the interested parties. It is also noted that the anti-dumping duty was based on a different investigation period, whereas the present safeguard duty being proposed is based on much more recent period. Further, the Domestic Industry is suffering injury despite the existing anti dumping duty. Therefore, there would not be dual protection against the same injury since the present investigation pertains to possible volume injury.
- ix) As regards the argument that there is no link between increase of imports in 2012–2013 and the deterioration of the financial situation which started in the financial year of 2010–2011 according to the petitioner himself, it is noted that the above clearly establishes the link between increased imports and serious injury to the Domestic Industry. The volume of imports of Sodium Nitrite decreased in 2010-11, but increased thereafter in 2011-12 and more significantly in 2012-13. As a result of significant surge in imports, the performance of the Domestic Industry followed the trend in imports, with improvement in 2010-11 with respect to most parameters, but subsequent deterioration in 2011-12 and 2012-13, thereby suffering serious injury.
- x) The issue that the Domestic Industry is trying to create monopoly is not found correct as, apart from Petitioner, there are three more known producers of the product and, in fact, one of the producers, M/s Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. (Earlier known as M/s. Punjab Chemicals and Pharmaceuticals ltd.), Chandigarh has supported the present petition, which is on record.
- xi) It is argued by the Interested Party that demand is more than supply. It is noted that due to increased imports on low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales in tandem with the rate of increase in consumption of product under consideration in India. However, the total all-Indian capacity to produce the product under consideration is sufficient to cater to the total demand in India.
- xii) It was argued by the interested parties that there is difference in technical specifications of the domestic and imported material. Moisture contents are high in Chinese products. Whereas, the domestic product have maximum 1% moisture, Chinese products have maximum 1.4% moisture. There is difference in the Drybase contents, purity, iron and insoluble-in-water contents also. However, no information was provided by the interested parties to substantiate their argument. In the absence of any information contrary to the claim of the Domestic Industry and considering that the imported and domestic product both are same sodium nitrite, it is held that domestically produced Sodium Nitrite falls under the ambit of like or directly

competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Sodium Nitrite is a like article to the imported Sodium Nitrite within the ambit of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules, 1997.

VI. **FINDING OF THE DIRECTOR GENERAL:**

- 21. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, user/importers, exporters and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below.
- 22. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
- 23. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.
- 24. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

A. The Product Under Consideration (PUC):

25. The product under consideration (hereinafter referred to as PUC) in the present case is 'Sodium Nitrite' (NaNO₂) classifiable under Customs Tariff Heading 28341010 of Chapter 28 falling under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. Sodium Nitrite is an oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder, mostly used in Pharmaceuticals industries for the production of Paracetamol, Analgin, Theophylline, Caffeine; Dye industries; Lubricants industry; Construction chemicals industry; Rubber blowing agent; Heat transfer salts, meat processing industry; Textiles, etc. Major raw material for production of Sodium Nitrite is Ammonia, which is converted into Nitrous Oxide at high temperature in presence of appropriate catalyst. No Interested Party raised any issue with regard to the product under investigation. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is "Sodium Nitrite" falling under Custom Tariff Heading 28341010 of Chapter 28 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Accordingly, it is also held that domestically produced Sodium Nitrite falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Sodium Nitrite is a like article to the imported Sodium Nitrite within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

B. Domestic Industry (DI):

- 26. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:
 - "(b) "Domestic Industry" means the producers —
 - (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
 - (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"
- 27. The application has been filed by M/s. Deepak Nitrite Limited, Pune 411006, a domestic producer of Sodium Nitrite (hereinafter referred as DI). As per records of the case, there are three other manufacturers of this product, namely, Punjab Chemicals & Crop Protection Limited, Chandigarh (UT), National Fertilizer Limited, Noida (UP), and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai (Maharashtra).
- 28. During post-Initiation, M/s Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd, Chandigarh (earlier known as M/s Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.) vide their letter dated 9th August, 2013 supported the application filed by M/s. Deepak Nitrite Limited and submitted their production and sales information for the year 2009-10 to 2012-13. It is found that there is no concept of supporter in safeguard investigation. Hence, they are not treated as Domestic Industry in subject investigation. However, being relevant to the issue at hand, the data submitted by them has been taken on record for injury analysis. The share of DI in the total production of the product in India varies from 88% to 85% during last three years as shown in the table below:

| Period | Production of | Production of | Total Indian | Share of DI in |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | DI (MT) | Others, including | Production (MT) | Indian Production |
| | | Supporter (MT) | | |
| 2009-10 | 29236 | 3955 | 33191 | 88.09 % |
| 2010-11 | 30473 | 4529 | 35002 | 87.06 % |
| 2011-12 | 30105 | 4660 | 34765 | 86.60 % |
| 2012-13 | 29661 | 5080 | 34741 | 85.38 % |

29. From the above table, it is noticed that the output of the applicant constituted a major share of the total production of Sodium Nitrite in India. Further, no claim has been made by the Interested Parties against the applicants being the Domestic Industry. Therefore, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act,1975.

C. Source of information:

- 30. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 2834.1010 of Chapter 28 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of DGCI&S, Kolkata till December, 2012. The import data from Jan, 2013 to March, 2013 has also been taken from the records of DGCI&S, Kolkata. The data on various economic parameters was submitted by the Domestic Industry in their petition till December, 2012. However, the data on various economic parameters till February, 2013 has been verified by this Directorate on the basis of central excise records of the petitioner in the month of March, 2013 to the extent possible. The data for March, 2013 in respect of various economic parameters as per central excise records has been taken as furnished by the applicant, duly certified, in order to arrive at yearly consolidated data for the year 2012-13 for injury analysis. The data for three years or longer has been provided by the DI in the form and manner decided by DG (Safeguard) under Rule 5(2) of Safeguard Duty Rules 1997 Vide Trade Notice No-SG/TN/1/97 dated 06/09/1997. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for all concerned. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner duly certified by an independent Cost Accountant.
- 31. It is also noticed that none of the interested parties have raised any objection to the import data considered or have provided information with regard to gross imports of Sodium Nitrite to India or have disputed the data furnished by the petitioner / DI.

D. Period of Investigation (POI):

32. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and

third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)⁹

33. The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)2

- 34. From the above it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation. However, in the spirit of the references cited above, it appears that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past, but the investigation period should be the recent past.
- 35. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered on year to year basis, from financial year 2009-10 to 2012-13. In the Notice of Initiation, import data up to December, 2012 had been considered on annualized basis. The import data has since been updated till March, 2013. Therefore, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2009-10 to 2012-13 for the purpose of the present investigations.

E. Confidentiality of information submitted:

- 36. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
- 37. The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application. which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

F. Anti-dumping Measures:

38. As on date, the subject PUC also attracts anti-dumping duty. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended, the Anti-dumping Authority notified its second sunset review Final Findings vide No.15/4/2010 – DGAD dated 30th June, 2011 and recommended continuation of definitive anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite originating in or exported from China PR and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No.76/2011-Customs dated 17th August, 2011. The Anti-dumping Authority has initiated a second sunset review of anti-dumping duty in force on imports of Sodium Nitrite from European Union vide Notification No 15/1009/2012-DGAD dated 23rd March, 2013 and the Central Government vide Notification No.04/2013-Customs(ADD) dated 10th April, 2013 extended the duty for further one year.

¹ WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-line Pipe case

² WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

G. Increased Imports:

- 39. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:
 - "(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"
- 40. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
- 41. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:
 - "(c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."
- 42. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC)¹⁰, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:
 - "131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharpenough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."
- 43. The Panel on US Wheat Gluten¹¹, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:
 - "8.31 [Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

a) Increased Import in absolute terms:

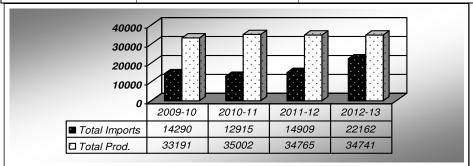
44. The analysis of the trend in imports of Sodium Nitrite in the light of the above mentioned provisions has been done. Sodium Nitrite is imported into India from a number of countries, and primarily from China and

¹⁰ Appellate Body Reports on Argentina-Footwear (EC) WT/DS 121/AB/R dated 14th December, 1999.

¹¹ Panel Report on US — Wheat Gluten WT/DS166/R 31 July 2000

Germany. The imports of Sodium Nitrite have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the domestic production and demand, causing injury and serious threat of injury to the Domestic Industry. The quantum of imports of Sodium Nitrite during 2009-10 to 2012-13 are as under:

| Financial Year | Total Imports (MT) | All India Production (MT) |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| 2009-10 | 14290 | 33191 |
| 2010-11 | 12915 | 35002 |
| 2011-12 | 14909 | 34765 |
| 2012-13 | 22162 | 34741 |

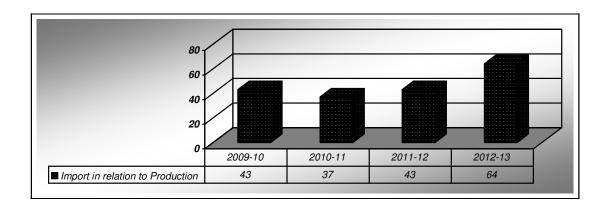


45. It is apparent from the data in the table above/graphical representation thereof that there is a surge in import in absolute terms. The imports have increased from 14290 MT in 2009-10 to 22162 MT in 2012-13, which shows an increase of 55%. There is a sudden surge in 2012-13 over 2011-12, by about 48%. There is a fall in import in 2010-11 from 2009-10, which is also the period for rise in domestic production. It is noticed that in 2010-11, whereas import price increased, the selling price of applicant did not increase. In 2011-12, applicant's price increased significantly, whereas there was mild increase in import price. This phenomenon appears to explain the reason for dip in imports volume in 2010-11 from the levels of 2009-10 and then to follow an increasing trend thereafter. It has been pointed out by the DI that on review of anti-dumping duty on the PUC from China, a higher rate of anti-dumping duty was imposed vide notification No. 143/09-cus dated 22/12/2009 than what was imposed vide notification No.03/06-cus dated 17/01/2006, which was, as contended by them, a cause for dip in import surge during 2010-11.

b) Import in relation to Production:

46. The imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to production of the Domestic Industry when compared with the base year. The import with respect to total production increased from 43% in 2009-10 to 64% in 2012-13, i.e., by 21%, which is a significant surge.

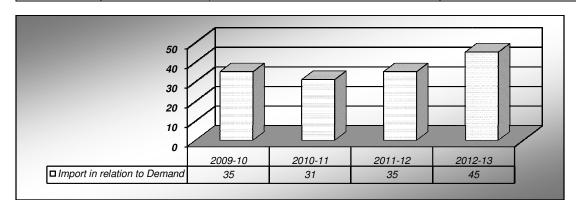
| Financial Year | Total Imports (MT) | All India Production (MT) | % of import with respect to production |
|----------------|-----------------------|------------------------------|--|
| 2009-10 | 14290 | 33191 | 43 % |
| 2010-11 | 12915 | 35002 | 37 % |
| 2011-12 | 14909 | 34765 | 43 % |
| 2012-13 | 22162 | 34741 | 64 % |



47. It is apparent from the above that there is a surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production and that the increase in imports has a rising trend which is significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Customs Tariff Act 1975

c) Import in relation to Demand:

| Financial Year | Total Imports (MT) | Total Demand including captive consumption (MT) | % of import with respect to Demand |
|-------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 2009-10 | 14290 | 41056 | 35 % |
| 2010-11 | 12915 | 41164 | 31 % |
| 2011-12 | 14909 | 42245 | 35 % |
| 2012-13 | 22162 | 49241 | 45 % |



48. For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is determined as the imports of product into India from different countries, domestic sales of the Domestic Industry (DI) and domestic sales of other domestic producers. Changes in demand/consumption so determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources and supplies by the Domestic Industry in order to determine whether imports of product under consideration in India have increased significantly in relation to consumption or demand for the product in the country. It is noticed in the table below that the import with respect to demand increased from 35% in 2009-10 to 45% in 2012-13, i.e., by 10%, which is a significant increase.

H. Reasons for increase in imports/Unforeseen developments:

49. It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules, on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments or the WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of

- GATT, however, obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.
- 50. The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.
 - 50.2 The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances":
- 51. The Domestic Industry has pointed out the following factors that have led to the increased imports of the product from China:
- a) Increase in capacity in China leading to diversion of export to India: The petitioner has submitted that the producers in the exporting countries, especially China, have created significant production capacities. Due to decline in demand in these countries, these producers are exporting huge volumes. The entire Indian demand can be met by exports from these countries. Petitioner further submitted that India has become the major export destination due to its growing demand. While exports from China to other countries have remained the same, the volume of exports from China to India has increased unexpectedly during the POI, especially in the last three years.

| Financial Year | Export from China to India (MT) | *Export from China to other countries (MT) |
|----------------|---------------------------------|--|
| 2010-11 | 6765 | 32,834 |
| 2011-12 | 9327 | 33,812 |
| 2012-13 | 18536 | 34,789 |
| Trend | | |
| 2010-11 | 100 | 100 |
| 2011-12 | 138 | 103 |
| 2012-13 | 274 | 106 |

*Source: China Customs

- b) Imposition of anti dumping duty by USA: Further, the United States has imposed anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite from China PR and Germany in the year 2008. Faced with loss of market opportunity in the market like the United States, the producers/exporters in China and Germany started exporting the product under consideration to India owing to its growing demand.
- 52. On examining the data given, it is noticed that producers in China and European Union in particular are targeting the Indian market. Excess capacities are present in the major exporting countries and it has been found that Indian demand/apparent consumption of Sodium Nitrite has been increasing. This indicates the reason for increase in imports. It is, therefore, seen that the above reasons cited by the Domestic Industry appear to constitute unforeseen development.

I. Serious Injury and Threat of Serious Injury: :

53. "Serious injury" ¹² means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry; and "threat of serious injury" ¹³ means a clear and imminent danger of serious injury.

¹² Section 8B(6)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

¹³ Section 8B(6)(d) of the Customs Tariff Act, 1975.

- 54. Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the Domestic Industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.¹⁴
- 55. Section 8B sub-section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

56. The Annex (1) to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

- 57. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.
- 58. It is held that the increased imports of Sodium Nitrite have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producer of Sodium Nitrite as indicated by the following factors:
- **a. Market Share:** Market share of domestic producers has fallen significantly as compared to imports. Applicants had a market share of 55% in 2010-11 which fell to 51% during 2011-12. The market share of the applicants further declined to 41% in 2012-13. On the other hand, the market share of import increases from 35% in 2010-11 to 45% in 2012-13.

| Financial Year | Total Import (MT) | Sales of DI (MT) | Sales of other Indian Producers (MT) | Total Demand including captive consumption (MT) | | Market are | Inventorie s (MT) |
|----------------|-------------------------|------------------------|--|---|----|---------------|----------------------|
| | | | | | DI | Import | |
| 2009-10 | 14290 | 21526 | 3959 | 41056 | 52 | 35 | 170 |
| 2010-11 | 12915 | 22673 | 4517 | 41164 | 55 | 31 | 186 |
| 2011-12 | 14909 | 21368 | 4667 | 42245 | 51 | 35 | 200 |
| 2012- 13 | 22162 | 20257 | 5047 | 49241 | 41 | 45 | 943 |

¹⁴ Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report of WTO

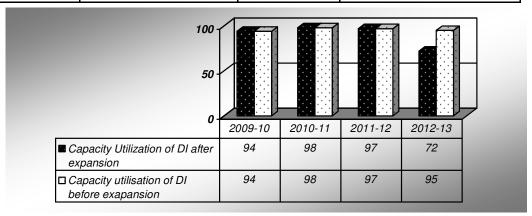
| 60 - 40 - 20 - 0 - | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Ü | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
| ■ Market Share of DI | 52 | 55 | 51 | 41 | |
| ☐ Market Share Imports | 35 | 31 | 35 | 45 | |

b. **Production:** Though the production of the Domestic Industry increased in 2010-11 compared to the year 2009-10, it declined from 30473 MT in 2010-11 to 30105 MT in 2011-12, and to 29661 MT in 2012-13.

| Financial Year | Production (MT) |
|----------------|-----------------|
| 2009-10 | 29236 |
| 2010-11 | 30473 |
| 2011-12 | 30105 |
| 2012-13 | 29661 |

c. Capacity Utilisation: Capacity utilization of the Domestic Industry has declined significantly in the most recent period, from 98% in 2010-11 to 72% in 2012-13. However, the total all Indian capacity to produce the product under consideration in the most recent period is sufficient to cater the total demand in India, but its utilization is a low 72%, which is shown as below:-

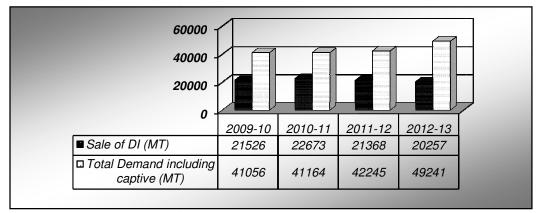
| Financial Year | Installed Capacity of DI (MT) | Capacity Utilized (%) | All Indian installed Capacity (MT) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 2009-10 | 31000 | 94 | 39500 |
| 2010-11 | 31000 | 98 | 39500 |
| 2011-12 | 31000 | 97 | 39500 |
| 2012-13 | 41124 | 72 | 49625 |



- (i) It is seen that additional capacities were added in 2012-13, but the actual volume of production in that year was lower than that in the previous year.
- (ii) In view of the submissions made by an Interested Party that lower utilization is due to increased capacity and given the fact that the Domestic Industry enhanced its capacity in 2012-13, it was considered prudent to examine whether the decline in capacity utilization was due to increase in capacity. It is, however, noted that had the Domestic Industry not enhanced its capacity, its utilization in 2012-13 would still have been 95% only which shows a declining trend in capacity utilization from 2010-11 onwards. Thus, it appears that the capacity utilization would have shown decline in any case, even if the Domestic Industry would not have enhanced the capacity.

- (iii) So far as the capacity utilization by the DI is concerned, it appears that the DI is facing lower capacity utilization due to rise in imports in the most recent period, irrespective of enhancement of capacity.
- d. Changes in the level of Sales: Though the sales of the Domestic Industry increased in 2010-11 as compared to the year 2009-10, it declined from 22673 MT in 2010-11 to 20257 MT in 2012-13. This decline in sales is despite the fact that the demand increased from 41164 MT in 2010-11 to 49241 MT in 2012-13. This clearly shows that the Domestic Industry suffered loss in sales and the market share at the cost of surge in imports in the wake of rising demand for the PUC as in the table below:-

| Financial Year | Sales of DI (MT) | Total Demand including captive consumption |
|----------------|------------------|--|
| | | (MT) |
| | | |
| 2009-10 | 21526 | 41056 |
| 2009-10 | 21526 | 41056 |
| 2010-11 | 22673 | 41164 |
| 2011-12 | 21368 | 42245 |
| 2012- 13 | 20257 | 49241 |



- e. **Employment:** There is no significant change in the level of employment and in productivity over the injury period. It has shown normal growth over the period. Applicant submitted that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the Domestic Industry.
- f. **Inventories:** With increase in imports and decline in domestic sales, the Domestic Industry has been forced to accumulate inventories. Closing stock has increased from 170 MT in 2009-10 to 200 MT in 2011-12, significantly increased to 943 MT in 2012-13, as shown below:-

| Period | Closing Inventories (in MT) |
|---------|-----------------------------|
| 2009-10 | 170 |
| 2010-11 | 186 |
| 2011-12 | 200 |
| 2012-13 | 943 |

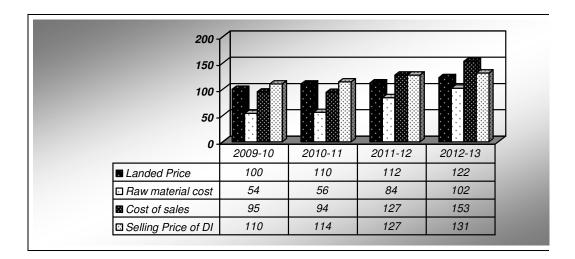
g. Profit & Loss: The profitability & returns on investments of the Domestic Industry has steeply deteriorated to such a situation that the Domestic Industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

| Financial Year | Profitability (Rs. /MT) | Return on Investments(%) | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | (Indexed) | (Indexed) | |
| 2009-10 | 100 | 100 | |
| 2010-11 | 133 | 149 | |
| 2011-12 | -4 | 4 | |
| 2012-13 | -144 | -102 | |

h. **Price undercutting, suppression/depression**: It is observed that the landed price of the imports of Sodium Nitrite is significantly lower than the selling price of the Domestic Industry. There is a significant price

difference between the domestic and imported product. The variation of prices of raw material, cost of sales and selling price with respect to landed prices of imports are as under:-

| SN | Particulars | Units | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|----|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Landed price of import | | | | | |
| 1 | (Indexed) | Rs/MT | 100 | 110 | 112 | 122 |
| 2 | Raw Material cost (Indexed) | Rs/MT | 54 | 56 | 84 | 102 |
| 3 | Cost of Sales (Indexed) | Rs/MT | 95 | 94 | 127 | 153 |
| 4 | Selling Price of DI | | | | | |
| 4 | (Indexed) | Rs/MT | 110 | 114 | 127 | 131 |



It is seen from the above table/graphical representation thereof, that whereas the cost of sales and the selling price both increased sharply during last two years, the rate of increase in the cost of Sales in 2012-13 over 2011-12 is far higher than the rate of increase in the selling price of the Domestic Industry during the same period. Moreover, it is also clear that the DI was posing profits till 2010-11 and suffered marginal losses in 2011-12. The increase in the selling price by the DI in 2012-13 over 2011-12 was 3.14%, much less than the rise in landed value of imports (9%) as against sharp rise in cost of sales (by 20.47%). The imports were thus suppressing the Domestic Industry prices in the market. It is seen that the prices of major inputs increased very significantly over the same period (by 21.43%) but the rise in cost of sales was lower than the rate of rise in raw materials showing that the Domestic Industry was prevented from raising its prices in proportion to the input cost increases as a result of increased imports, causing serious injury.

J. Conclusion Regarding Serious Injury:

- 59. The imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The volume of imports of Sodium Nitrite decreased in 2010-11, but increased thereafter in 2011-12 and more significantly in 2012-13. As a result of significant surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury. Performance of the Domestic Industry followed the trend in imports, with improvement in 2010-11 with respect to most parameters and subsequent deterioration in 2011-12 and 2012-13.
- 60. Market share, production, domestic sales, capacity utilization, productivity, profit/loss, profitability, cash profits and return on investment have improved in 2010-11, but subsequently declined in 2011-12 and further in 2012-13. Inventories with the Domestic Industry have increased throughout the injury period, with a significant increase in 2012-13. Price undercutting was seen throughout the period. Further, the imports are preventing the price increase by the Domestic Industry in proportion to increase in cost.
- 61. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows 'a significant overall impairment'. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration.

K. Threat of Serious Injury:

- 62. There is threat of serious injury to the Domestic Industry producing Sodium Nitrite in India due to the surge of imports and the current trend of import volumes entering India. Imports are entering India in increasing absolute volumes. The market share of imports has also substantially increased over the period. Considering the production capacities available with foreign producers and their export orientation, there is a high likelihood of continued increase in imports.
- 63. The price difference between domestic sales and imports of Sodium Nitrite renders the Indian market an attractive destination for exports. Any further increase in imports as a result of this will threat further serious injury to the Domestic Industry. It is noted in this regard that the imports are undercutting the net selling price of the Domestic Industry.
- 64. In light of the current financial situation of the Domestic Industry in terms of profitability, and return on investment, it is concluded that in the absence of levy of safeguard duty, the Domestic Industry faces a threat of serious injury

L. Other factors causing serious injury or threat thereof:

- 65. Para (2) of Annex to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 lays down that the determination referred to in subparagraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased import are causing "serious injury" to the Domestic Industry at the same time, such "serious injury" shall not be attributed to increased imports.
- 66. As such, the possible other factors that may be attributed to the serious injury to Domestic Industry have been examined. Followings are relevant in this regard:
 - a) Demand of the product: When overall demand increases, it is expected that, in tandem therewith, sales of the domestic industry will show rising trend; may be imports too show such a trend. However, in this case, market share of the DI has shown a decline whereas the market share of imports has risen. It is, thus, clearly seen that the increased imports have taken away the major share of the demand.
 - b) Changes in the patterns of consumption: It is claimed by the Domestic Industry that there is no evidence on record that the pattern of consumption with regard to the product under consideration has undergone any material change as far as the Indian market is concerned. None of the Interested Parties has also brought out any evidence to dispute this claim of the Domestic Industry, and is, as such, accepted.
 - Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

 There is no evidence on record that trade restrictive practices or competition between the foreign and domestic producers could have contributed to the injury to the Domestic Industry. However, it is a fact that the volume injury is there, even after imposition of anti dumping duty on this product.
 - d) **Export performance**: Applicants have exported small volumes of the product under consideration. However, the claimed injury to the Domestic Industry is on account of domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic operation. No evidence has been put forth by any Interested Party about non- supply of PUC by the DI, citing export requirement or vice-versa. Claimed injury to Domestic Industry, therefore, cannot be attributed to exports, which is thus accepted.
 - e) **Developments in technology**: The applicant has claimed that the technology for production of the product has not undergone any change. This has not been refuted by any Interested Party. Developments in technology are therefore, not a factor of injury, in this case.
- 67. It is thus noted that possible other factors have not caused injury to the Domestic Industry. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the Domestic Industry other than dumping and surge in the low priced imports.

M. Causal Link between Increased Import and Serious injury or Threat of Serious injury:

68. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.

To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors." ¹⁵

- 69. A comprehensive evaluation of parameters as above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard
 - Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly;
 - ii) As the imports are available at prices lower than the selling price of Domestic Industry, the consumers are switching over to imports due to which the Domestic Industry is faced with losing sales and rising inventory;
 - iii) Price undercutting being caused is preventing the Domestic Industry from increasing its prices in proportion to increase in cost of sales;
 - iv) The price suppression effect of dumped imports was on significant decline in profitability to the Domestic Industry to such an extent that Domestic Industry suffered huge losses in the recent period;
 - v) Market share of imports increased and, consequently, market share of the Domestic Industry declined;
 - vi) Due to increased imports on low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales in tandem with the rate of increase in demand/consumption of product under consideration in India:
 - vii) The production, capacity utilization, profits, return on investment, all declined due to increased imports.
- 70. It is thus evident that serious injury to the Domestic Industry has been caused by the increased imports which is also threatening to cause injury.

N. Public Interest:

71. Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest.

Panel Report on Korea - Dairy, paras. 7.89-7.90

The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

- 72. In an economy there are varying and sometimes competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore, interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information.
- 73. The landed price of imports is lower than the (a) selling price of the Domestic Industry, and (b) cost of sales of the Domestic Industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression. It is seen that the selling price of the Domestic Industry is far lower than the cost of sales. In order to sustain in the market, the Domestic Industry was unable to increase its selling price in proportion to increase in cost of sales thereby suffering huge losses in recent period. With the rate of decline in profits and return on investments, with non levy of safeguard duty, the Domestic Industry, as claimed by them, would be left with no option but to close down its business.
- 74. It has been claimed by the Domestic Industry that the imposition of safeguard duty would be in public interest as it will not only prevent injury to the Domestic Industry but also would help in checking further decline of the Domestic Industry. As regards the impact of safeguard duty on consumers/users, it is observed that Sodium Nitrite is primarily consumed in Pharmaceuticals industries for production of Paracetamol, Analgin, Theophylline, Caffeine, Dye industries, Lubricants, Construction chemicals, Rubber blowing agent, Heat transfer salts, meat processing, Textiles, etc.
- 75. The Domestic Industry has cited an example and has tried to quantify the impact of 20% safeguard duty on eventual downstream products claiming that the 20% increase in price on account of safeguard duty, if fully passed onto the eventual end product (assuming that the Domestic Industry increases the prices by 20%) would have minimal impact on the eventual end products, as is seen from the following table:-

| Sector-wise PUC | Consumption and | Cost per Unit | t of the Finish Goods |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|

| SN | Segment | SNI % used in Finished products | Usage | Impact @ 20% | Average impact of duty |
|----|--|---------------------------------|-------|--------------|------------------------|
| Α | В | С | D | E=C*20% | F=D*E |
| 1 | Dyes & Pigment | 1.93% | 70% | 0.387% | 0.271% |
| 2 | Pharma | 3.45% | 18% | 0.691% | 0.124% |
| 3 | Rubber Blowing Agent | 20.71% | 5% | 4.143% | 0.207% |
| 4 | Heat Treatment | 14.00% | 7% | 2.800% | 0.196% |
| | Weighted average impact of duty on the consumers | | | | |

- 76. The above claim of Domestic Industry has not been disputed by Interested Party in these investigations. In view of the absence of any contrary submissions/rejoinders having been filed by any Interested Party in this case, the submissions made by the Domestic Industry are considered justified. As shown by the Domestic Industry, it appears that the impact of the safeguard duty on different segments of the users of the subject product would be minimal. It is concluded that even if the prices are increased by 20%, the impact of the same on the eventual end product would not be significantly adverse, and that the imposition of the safeguard duty will not result in significant increase in the prices of eventual end products.
- 77. In the light of the facts on record, it is concluded that imposition of safeguard duty would be in public interest and the interests of end users would not be very adversely impacted.

O. Adjustment Plan:

- 78. Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
- 79. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.
- 80. The domestic producers in this case has laid down adjustment plan which focuses on:
 - (i) Cost reduction
 - (ii) Further utilization of existing production capacity
 - (iii) Capacity expansion to cater the growing demand
- 81. The Applicant submitted that they have set up another manufacturing facility within the present location in the month of Nov, 2012 wherein the company intends to produce 18150 MT of product under consideration. The plant has commenced trial production in Nov-Dec 2012 but was unable to continue the commercial production owing to increased imports causing significant injury. As rising imports affected the capacity utilization of the existing plant over the POI, it was decided by the DI that commencing commercial production in a new plant would be disastrous. As submitted, the Applicant hopes that the new Plant will be fully operational at optimum capacity once the protection is granted under safeguard duty, and that the expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of Sodium Nitrite in the Country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand. It is further stated that steps towards cost cutting is already in place, the plant expansion would enable the company to face fair competition from imports. Accordingly, the petitioner has requested safeguard duty for a period of two years so that they are in a position to face the import competition.
- 82. It is further clarified by the applicant that owing to the above adjustment plan, the company would be in fair position to meet the international competition as well as will be able to meet the potential demand of subject goods in India. In view of the above, it appears that the applicant has provided a viable adjustment plan which focuses on cost reduction, optimum utilization of production capacities to cater the growing demand of Sodium Nitrite.

P. Developing Nations:

83. The percentages of imports from developing nations have also been examined. Except China PR who constitutes 81% of total imports in India during FY 2012-13, other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports in India. Therefore, imports of product under consideration originating from developing nations except China PR may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

Q. Conclusion:

- 84. On the basis of above examination and analysis done, it is concluded that :
 - a. There has been a significant increase in imports of Sodium Nitrite, the Product Under Consideration (PUC) in absolute terms as well as in relation to domestic production over the entire Period of Investigation (POI). Thus, it can be concluded that there is a significant surge in imports of PUC in the most recent period so as to cause or threaten to cause serious injury. This surge in imports is also quite significant in relation to production as well as in relation to total demand.
 - b. The Domestic Industry has been able to demonstrate that the developments in the market for the Product under Consideration were unforeseen, especially with regards to China PR (83% of total imports) and European Union (16% of total imports).
 - c. The Domestic Industry has shown serious injury on account of overall economic parameters, i.e., market share, sales, capacity utilization, profitability, production and inventory. However, the injury in case of production and inventory in absolute terms is marginal. As the rising imports have affected the demand in

the country considerably, the domestic industry has faced problems due to loss in market share to imports. The DI has been able to demonstrate serious injury caused in the form of mounting losses and accumulated inventories by way of declining sales even when demand for the PUC rose in the country. It establishes the causal link between the rise in imports and serious injury caused to the Domestic Industry during the POI.

- d. It is also seen that the Domestic Industry has sought protection in the form of Safeguard Duty for a period of 2 years, for which they have provided an adjustment plan. This adjustment plan has not been disputed or refuted by any Interested Party during the entire course of investigation and is also found to be reasonable. The contention of the Domestic Industry that they have already expanded their capacity and are fully capable to cater to the demand of the product under consideration in the domestic market along with other domestic producer, appears acceptable.
- e. It is also on record that the PUC, i.e., Sodium Nitrite is already subjected to anti-dumping duty vide notification no.76/2011 customs dated 17th August,2011 (from China PR) and vide notification no. 04/2013 customs (ADD) dated 10th April,2013 (from European Union) till 10th April,2014. During the present investigations, it has been noticed that the Domestic Industry has protection in the form of anti-dumping duty for the subject PUC, but, despite this, they have still suffered serious injury due to surge in imports of the PUC in the country, which, therefore, requires protection in the form of Safeguard duty, so as to offset serious injury caused and threat of causing of serious injury due to surge in imports. Thus, there is a clear case of imposition of safeguard duty, irrespective of whether or not the PUC is liable to anti-dumping duty, i.e., safeguard duty has to be over and above anti-dumping duty, if leviable.
- f. The Domestic Industry has also been able to show that imposition of safeguard duty in this case would be in Public Interest because the probable impact of the safeguard duty on end users/consumers would be minimal. It is also found that no Interested Party has refuted or disputed this aspect during the course of investigation.

R. Recommendations:

85. Increased imports of Sodium Nitrite into India have therefore, caused and threaten to cause serious injury to the domestic producers of Sodium Nitrite and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Sodium Nitrite into India, in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997, for a period of one year and three months. Considering the average cost of sales of Sodium Nitrite by the domestic producers, after allowing a reasonable return on capital employed, safeguard duty at the rate of 30% *ad valorem* for the first year and 28% *ad valorem* for the second year (for three months only), which is considered to be the minimum required to protect the interest of Domestic Industry, is hereby recommended to be imposed on imports of Sodium Nitrite falling under Custom Tariff Heading 28341010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, as shown below:-

| Period | Rate of Safeguard Duty |
|-------------------------------------|------------------------|
| First year | 30% ad valorem |
| Second year (for three months only) | 28% ad valorem |

86. As the imports from developing nations except China PR do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No. D-22011/03/2013/1494]

RAM TIRATH, Director General